04 - मार्च 2026 के पहले नक्सलवाद का खात्मा संभव

05 - पर्यटन में भी सूखा झेल रहा है बुंदेलखंड

06 - परिवार को बंधक बनाकर नकाबपोशों ने की लाखों की डकैती

07 - नर्मदापुरम की भूमि उपजाऊ एवं समृद्ध है जिले के विकास में...

सुबह सवेरे

A Daily News Magazine
भोपाल
शुक्रवार, 23 मई, 2025

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 253, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

अगर कांग्रेस शशि थरूर को खो देती है तो क्या होगा?

डीके सिंह

क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ग्लोबल आउटरीच के लिए सभी दलों के प्रतिनिधिमंडलों में विपक्षी सांसदों और नेताओं को चुनकर राजनीति की? हां, बिल्कुल। जब सरकार ने पहले ही कांग्रेस के प्रतिनिधियों को तय कर लिया था और मंत्री चार कांग्रेस नेताओं–शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और अमर सिंह–से बात भी कर चुके थे, तो फिर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को फोन करने का क्या मतलब रह गया?

अगर सरकार को इन चार नेताओं को ही प्रतिनिधिमंडल में शामिल करना था, तो वह कांग्रेस नेतृत्व से सीधा अनुरोध कर सकती थी कि इन्हें ही नामित किया जाए। लेकिन इसके बजाय रिजिजू ने खड़गे और गांधी के प्रतिनिधि भेजने का इंतज़ार किया और फिर सरकार ने अपने हिसाब से कांग्रेस के नाम घोषित कर दिए।

भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को पहले से अंदेशा था कि कांग्रेस थरूर, तिवारी और बाकी दो को नामित नहीं करेगी। कांग्रेस इस जाल में फंस गई। अब मुख्य विपक्ष पार्टी की स्थिति शर्मनाक हो गई है। पार्टी के अंदरूनी मतभेद भी खुलकर सामने आ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम यह चर्चा करें कि कांग्रेस हाईकमान ने कैसे गड़बड़ी की, यह साफ़ होना चाहिए कि सरकार ने विपक्ष को राजनीतिक मकसद से इस्तेमाल किया। सरकार के प्रचार तंत्र से इस बात पर बहस नहीं की जा सकती कि शशि थरूर, जो संसद की स्थायी समिति (विदेश मामलों) के अध्यक्ष हैं और जो संयुक्त राष्ट्र में लगभग तीन दशक तक काम कर चुके हैं, अमेरिका और अन्य देशों में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे।

अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शशि थरूर अच्छे लगने लगे – यह उस वक्त हो रहा है जब मुख्य विपक्षी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के विश्वगुरु नारे को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। उधर सरकार ने भी अपनी चाल चल दी है। 45 सांसदों और 6 वरिष्ठ नेताओं वाले सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा – जो 33 देशों की राजधानियों में जा रहे हैं, विपक्ष के हमले की धार को कम करने की कोशिश है। इन प्रतिनिधिमंडलों में 19 विपक्षी नेता हैं – जिनमें से ज़्यादातर मुखर और तर्कशील माने जाते हैं। सोचिए, थरूर, तिवारी और कांग्रेस के तीन और नेता विदेशों में भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और सरकार के रुख का समर्थन करेंगे, जबकि देश में उनकी ही पार्टी सरकार को अंतरराष्ट्रीय समर्थन न मिल पाने के लिए कोस रही है।

ऑल पार्टी डेलिगेशन में कांग्रेस के साथ मोदी सरकार ने राजनीति की, ये तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस इस चाल में फंसी क्यों?

शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे नेता तो अपनी बात साफ- साफ कहने के लिए जाने जाते हैं, खासकर जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो। उन्हें गांधी परिवार की तरह अल्पसंख्यक बहुल वायनाड जैसी सुरक्षित सीटें नहीं मिलतीं। थरूर और तिवारी जैसे नेता अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक मंचों पर सम्मानित और प्रभावशाली आवाज़ें हैं। सलमान खुर्शीद तो पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। ये नेता कांग्रेस की तरफ से डेलिगेशन में नामित होने के स्वाभाविक विकल्प थे। फिर कांग्रेस ने इन्हें अपनी सूची से बाहर रखकर झटका क्यों दिया? सीधा जवाब है–छोटापन और निजी स्वार्थ। राहुल गांधी और उनके परिवार के आसपास जो एक गिरोह है, वही उन्हें असुरक्षित महसूस कराता है और सच्चाई नहीं देखने देता कि ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं।

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने थरूर को लेकर एक के बाद एक टिप्पणी करके कैसे उनकी छवि को ठेस पहुंचाई। रमेश ने कहा कि थरूर जो भी बोलते हैं, वह उनका निजी विचार है, पार्टी का नहीं। रमेश की दूसरी

टिप्पणियां भी देखिए: कांग्रेस एक विशाल गंगा की तरह है, जिसकी कई सहायक नदियां हैं- कुछ सूख जाती हैं और कुछ प्रदूषित हो जाती हैं। तो फिर एक 'प्रदूषित' शशि थरूर को इस गंगा की सहायक नदी बने रहने की क्या जरूरत है? थरूर कहते हैं कि उन्हें आसानी से अपमानित नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी पार्टी उनकी सहनशीलता की परीक्षा ले रही है। सबको पता है कि इस अपमान के पीछे कौन है। वो हैं केसी वेणुगोपाल, जो संगठन के महासचिव हैं और राहुल गांधी पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। वेणुगोपाल की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं है। इसलिए उन्हें हर संभावित प्रतिद्वंद्वी–सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी थरूर–को रास्ते से हटाना है। अब जब मोदी सरकार को इसमें मौका दिखा, तो उसने फायदा उठा लिया। तो फिर बीजेपी को दोष क्यों देना?

केरल में भी पंजाब जैसा ही प्लॉट तैयार हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल के प्रति बेहद मोहग्रस्त हैं। हाईकमान ने पंजाब में अमरिंदर सिंह को इतना अपमानित किया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और पार्टी छोड़ दी। अब केसी-जयराम एंड कंपनी थरूर के साथ भी वैसा ही कर रही है, ताकि वह भी जल्दी या देर से यही कदम उठाएं। पार्टी केरल में जीते या हारे–किसे फर्क पड़ता है? थरूर के पास क्या विकल्प हैं? उनके पास मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। क्यों न हो? आखिरकार, वह ऐसे नेता हैं जिन्हें जाति की सीमाओं से परे युवा पसंद करते हैं। केरल की दो प्रमुख अल्पसंख्यक आबादी–ईसाई और मुस्लिम, जो कुल जनसंख्या का 45 प्रतिशत हैं–थरूर के उदार विचारों और सोच के कारण उन्हें पसंद करते हैं। नायर सर्विस सोसाइटी, जो केरल की दूसरी बड़ी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, उन्हें अपनाने के लिए तैयार है। वहीं, एझवा समुदाय, जो केरल का सबसे बड़ा हिंदू समुदाय है और परंपरागत रूप से वामपंथ के साथ रहा है, उसमें अब वफादारी बदलने के संकेत दिख रहे हैं।, जो लोग मानते हैं कि थरूर के पास बीजेपी में जाने का विकल्प नहीं है, वे गलत हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम सीट पर थरूर और उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर के बीच का अंतर–करीब 16,000 वोट था। इनमें से बड़ी संख्या में कांग्रेस के वोटर असल में थरूर के वोटर थे। तो जब कोई कहता है कि थरूर बीजेपी में नहीं जा सकते, तो सीधा सवाल बनता है–क्यों नहीं? उनकी संसदीय सीट सुरक्षित रहेगी। कांग्रेस तो उन्हें सीएम चेहरा बना नहीं रही। तो अगर वो बीजेपी के सीएम उम्मीदवार बनते हैं, तो उन्हें क्या नुकसान है?

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

अब मोदी की नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा

- बीकानेर से पीएम ने पाकिस्तान को लगाई जमकर लताड़
- पीएम ने कहा-हमारी सेना पाकिस्तान को घुटनों पर लाई
- प्रधानमंत्री ने कहा-आईसीयू में है रहीमयार खान एयरबेस

बीकानेर (एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बीकानेर आए। जिला मुख्यालय से 22 किमी दूर देशनोक के पलाना में हुई सभा में मोदी करीब 40 मिनट बोले। उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। भारतीयों की जान से खेलने वालों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का लहू बहाने वालों को कतरे-कतरे का हिसाब चुकाना पड़ेगा। पीएम बोले-तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी और तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।

22 मिनट में नौ आतंकी ठिकाने कर दिए तबाह

पहलगाम हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह किए। दुनिया ने देखा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पांच साल पहले बालाकोट में देश ने एयरस्ट्राइक की थी। उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में हुई थी। वीर भूमि का ही ये तप है कि ऐसा संयोग फिर बना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर में सभा हो रही है।

- **मोदी की नस में खून नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है–** पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता। इसलिए आतंकवाद को भारत के खिलाफ हथियार बनाया है। पाकिस्तान एक बात भूल गया कि अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तानकर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म है। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कीमत पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा, ये भारत का संकल्प है।

देश के 103 अमृत स्टेशनों का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण, इनमें 6 एमपी के

अमृत स्टेशन देश के विकास का प्रवेश द्वार सिद्ध होंगे : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में भारत माता के जयकारों के बीच कहा कि विकसित भारत का संकल्प और मजबूत हो रहा है। देशभर में विकास का महायज्ञ चल रहा है, हमारी सड़कें और रेलवे नेटवर्क विकसित हों, इसके लिए 11 सालों में अभूतपूर्व काम हुआ है। विकास कार्यों पर देश पहले से 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। भारत में विकास कार्यों को देखकर दुनिया हैरान है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम से देश के 103 अमृत स्टेशनों के वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हो कर उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के नर्मदापुरम, कटनी, ओरछा, सिवनी, शाजापुर और श्रीधाम अमृत स्टेशनों का उद्घाटन हुआ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) के तहत देशभर के 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण किया। इनमें मध्यप्रदेश के 6 स्टेशन- नर्मदापुरम, श्रीधाम, कटनी साउथ, शाजापुर, सिवनी और ओरछा शामिल हैं।

कार्यक्रम में राजस्थान के बीकानेर से वर्चुअली जुड़े मोदी ने कहा- भारत में हो रहे विकास कार्यों को देखकर दुनिया हैरान है। वंदे भारत, नमो भारत ट्रेन देश की नई गति को दर्शाती है। अमृत भारत स्टेशन योजना में देशभर के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बना रहे हैं। विकास भी, विरासत भी मंत्र का इन स्टेशनों पर नजारा साफ दिखाई देता है।

सभी स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इन स्टेशनों में भारतीय संस्कृति, विरासत और यात्री सुविधाओं का समावेश किया गया है। बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, रेलमंत्री श्री अश्विनी वैषव, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल उपस्थित थे। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन के उद्घाटन समारोह में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री डॉ. राकेश सिंह, सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री सीताशरण शर्मा तथा स्थानीय विधायक उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) के तहत भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में स्थित 103 अमृत स्टेशनों को 1100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है।

- **प्रदेश के नर्मदापुरम, कटनी, ओरछा, सिवनी, शाजापुर और श्रीधाम अमृत स्टेशनों का हुआ उद्घाटन**
- **मुख्यमंत्री डॉ. यादव नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में हुए शामिल**

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को आधुनिक कर रहा है। वंदेभारत, अमृत ट्रेन और नमो ट्रेनें भारत की नई गति को दर्शाती है। देश के 70 रुटों पर वंदेभारत ट्रेन चल रही हैं। 34 हजार किलोमीटर से ज्यादा के नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। ब्रॉडगैज ट्रैकों पर मानव रहित क्रॉसिंग अब इतिहास बन चुका है। देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। हम 1300 से अधिक स्टेशनों को आधुनिक बना रहे हैं। इन्हें अमृत भारत स्टेशन नाम दिया गया है, इनमें से 103 स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं। इन स्टेशनों पर विकास भी और विरासत भी का नजारा दिखाई देता है। ओरछा स्टेशन पर भगवान श्रीराम की छवि दिखाई देगी। इसी प्रकार सभी स्टेशनों पर हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन होंगे। ये स्टेशन राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देंगे और युवाओं को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। साथ ही देश के चिनाब नदी पर बना रेलवे ब्रिज, मुंबई में अटल सेतु, दक्षिण में पंबन ब्रिज देखने को मिलेगा।

सुप्रभात

सब तुम्हारी ज़िम्मेदारी , याद रखना
धूप , बारिश और क्यारी , याद रखना
आसमां पंछी को कुछ आगाह कर दे
ताक में बैठे शिकारी, याद रखना
छूट जाए आधुनिकता में नहीं वो
सभ्यता की बात सारी, याद रखना
औपचारिक दोस्तों की भीड़ मे तुम
'जा ,बे,जा' वाली ये यारी,याद रखना
इक तरफ़ दुनिया –जहाँ के हैं समंदर
इक तरफ़ वो अश्क भारी,याद रखना
सूरतों के बीच यूं आला है सूरत
हमने है सीरत संवारी,याद रखना।

– वर्षा शर्मा

विचारधारा के चलते किसी को जेल में नहीं डाल सकते

- सुप्रीम कोर्ट बोला-देश में हम इस तरह का चलन देख रहे
- केरल के आरएसएस नेता हत्या मामले में आरोपी को जमानत

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि किसी को विचारधारा के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने यह टिप्पणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक नेता की हत्या के आरोपी को जमानत देते हुए की। सुनवाई के दौरान नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी के वकील ने कहा कि विचारधारा गंभीर अपराधों की ओर ले जाती है। इस पर कोर्ट ने कहा- आप किसी को उसकी विचारधारा के लिए जेल में नहीं डाल सकते। हम यह चलन देख रहे हैं। किसी ने एक खास विचारधारा अपना ली, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। साल 2022 में केरल के

पलक्कड़ जिले में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या हुई थी। मामले में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की केरल यूनिट के तब के महासचिव अब्दुल साथर को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट बोला- प्रक्रिया सजा नहीं बन सकती एनआईए के वकील ने दलील दी कि भले ही एफआईआर में साथर का नाम नहीं है, लेकिन संघ महासचिव के तौर पर उसने कैडरों की भर्ती और हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने जैसे काम किए। उस पर 71 मामले दर्ज हैं। साथर की ओर से पेश वकील तर्क दिया कि सभी मामले हड़ताल की घटनाओं से जुड़े हैं। इन सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है।

बड़े पर्दे पर दिखेगी भारत के 'मिसाइल मैन' की कहानी

- **धनुष निभाएंगे डॉ. अब्दुल कलाम का रोल, 'तानाजी' फेम ओम राउत करेंगे निर्देशन**

मुंबई (एजेंसी)। कान्स फिल्म फेस्टीवल 2025 में एक बेहद खास फिल्म का ऐलान हुआ है। इस फिल्म में भारत के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी को बड़े पर्दे पर उतारा जाएगा। इस फिल्म में नेशनल अवॉर्ड विनर और साउथ के सुपरस्टार धनुष डॉ. कलाम की भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन ओम राउत करेंगे, जिन्होंने 'तानाजी- द अनसंग वॉरियर' जैसी फिल्म बनाई है। वहीं, फिल्म को अभिषेक अग्रवाल (द कश्मीर फाइल्स फेम) और टी-सीरीज के भूषण कुमार प्रोड्यूस करेंगे। रॉकेट साइंटिस्ट से राष्ट्रपति बनने का सफर गौरतलब है कि डॉ. कलाम का जीवन

एक प्रेरणा है। रामेश्वरम के एक सामान्य परिवार से निकलकर उन्होंने इसरो और डीआरडीओ जैसी संस्थाओं में बड़ा योगदान दिया। मिसाइल प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई और भारत को न्यूक्लियर ताकत बनाया। बाद में वे देश के राष्ट्रपति बने और हमेशा लोगों के बीच रहे। अब कलाम का किरदार निभाएंगे धनुष धनुष ने अब तक कई बेहतरीन किरदार निभाए हैं। उनकी असुरन, मारी, वेलैला पट्टाधारी (वीआईपी) जैसी फिल्में साउथ सिनेमा में ब्लॉकबस्टर रही हैं। उन्होंने बॉलीवुड में भी रांझणा में अपने किरदार ने सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने अतरंगी रे में भी काम किया। फिल्म को लेकर ओम राउत का कहना है कि इस फिल्म को बनाना उनके लिए एक कलात्मक चुनौती और सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। फिल्म की स्क्रिप्ट और मेकिंग इस फिल्म की स्क्रिप्ट साइविन क्वाड्रास ने लिखी है, जिन्होंने नीरजा, मैदान और परमाणु जैसी बायोपिक लिखी हैं। एक शायर, शिक्षक और सपने देखने वाले इंसान की झलक भी मिलेगी।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 38 °c | न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार, 23 मई 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

नंगल डैम पर केंद्रीय बलों की तैनाती को मंजूरी

● पंजाब-हरियाणा के पानी विवाद के बीच केंद्र का बड़ा फैसला

चंडीगढ़ (एजेंसी)। नंगल डैम की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए गृह मंत्रालय ने बुधवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 296 जवानों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पंजाब और हरियाणा सरकारों के बीच भाखड़ा डैम के पानी को लेकर तनाव अपने चरम पर है। रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, इन जवानों को 2,90,100 रुपये प्रति जवान के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसके लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को केंद्र सरकार को कुल 8.58 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराने को कहा गया है।

मोदी सरकार राज्यपालों का कर रही है दुरुपयोग

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यपालों का गलत इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी के अनुसार, ऐसा करके निर्वाचित राज्य सरकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे

संघवाद पर एक खतरनाक हमला बताया और कहा कि इसका विरोध होना चाहिए। हर भारतीय राज्य की अपनी आवाज है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में यह बात कही। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के एक पोस्ट को टैग करते हुए इस तरह के दावे किए हैं। स्टालिन ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के एक फैसले की आलोचना की थी। राहुल गांधी ने लिखा है, भारत की ताकत उसकी विविधता में है...राज्यों का एक संघ, जिसमें हर राज्य की अपनी आवाज है। इसका मतलब है कि भारत अलग-अलग राज्यों से मिलकर बना है और हर राज्य का अपना महत्व है।

भारतीय नेवी में नया शिप शामिल, नाम-आईएनएसवी कौंडिन्य

नई दिल्ली (एजेंसी)। सिलकर बनाया गया शिप इंडियन नेवल सेलिंग वेसल कौंडिन्य आज इंडियन नेवी के जहाजी बेड़े में शामिल हो गया। कारवाड़ नेवल बेस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। इसका नाम भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है। उन्होंने हिंद महासागर को पार

करके साउथ-ईस्ट एशिया की यात्रा की थी। नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि साल के अंत में यह गुजरात से ओमान तक के पारंपरिक ट्रेड रूट पर ट्रांस-ओशनिक यात्रा करेगा। आधुनिक वेसल (पोत) से अलग इस सिले हुए जहाज में चौकोर पाल और स्टीयरिंग बोर्ड लगा है। स्टीयरिंग बोर्ड का उपयोग पतवार के आविष्कार से पहले जहाज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। इसके अलावा शिप के पाल पर गंधभेरुंड (दैवीय पक्षी) और सूर्य की आकृतियां हैं। उसके बो पर नक्काशीदार शेर और डेक पर हड़प्पा शैली का पत्थर है।

ऑपरेशन-सिंदूर के पोस्टर में पीएम की फोटो पर सियासत

शिमला (एजेंसी)। हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर सवाल उठाए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, हम देश के

पीएम का सम्मान करते हैं, पर उन्हें इस तरह के होर्डिंग्स लगाने से परहेज करना चाहिए। विक्रमादित्य आगे लिखते हैं, हो सकता है कि यह उनके निर्देशों पर नहीं किया गया हो, पर इन्हें उतारने के भी आदेश दिए जा सकते हैं। मंत्री ने लिखा कि ऐसा करने से जवानों का मनोबल गिरेगा। आखिर में विक्रमादित्य सिंह, प्रधानमंत्री को नसीहत देते हैं कि कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती हैं।

पशुपति से तिरुपति तक 'लाल सलाम' पर ठोंकी आखिरी कील

● इतिहास रचने के करीब अमित शाह, नक्सल मुक्त भारत के सपने की बढ़ी उम्मीद

नागपुर/गढ़चिरौली (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ में 27 नक्सलियों के एनकाउंटर ने लाल सलाम का सपना बुनने वालों के अरमानों के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। भारत में नक्सलवाद के कभी पशुपति से लेकर तिरुपति तक लाल सलाम की तैयारी की थी लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को गिने-चुने जिलों में सीमित कर दिया है। 27 नक्सलियों का एनकाउंटर भले ही छत्तीसगढ़ में हुआ है। इसकी गूंज महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में है। 1.5 करोड़ के इनामी बसवराजू नक्सल सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती था। वह महाराष्ट्र के 15 कमांडो का हत्यारा था। पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर बीच में सुशील कुमार शिंदे और फिर बाद में राजनाथ सिंह समेत 30 नेता गृह मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं, लेकिन देश के 31वें गृह मंत्री अमित शाह के दूसरे कार्यकाल में नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार प्रभावी तौर पर नक्सलियों का प्रभाव सिर्फ आधा दर्जन जिलों में रह गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलियों के बड़े नेता बसवराजू के मारे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। उन्होंने लिखा है कि नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि। आज, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में, हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया है, जिनमें सीपीआई-माओवादी के महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू भी शामिल हैं। नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के तीन दशकों में यह पहली बार है कि हमारे बलों द्वारा एक महासचिव स्तर

के नेता को मार गिराया गया है। मैं इस बड़ी सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूं। यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के पूरा होने के बाद, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मोदी सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। केंद्रीय गृह मंत्री के संकल्प में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने समर्थन दिया है। अमित शाह ने भले ही नक्सलियों के कमर तोड़ने का श्रेय सुरक्षाबलों को दिया है लेकिन एक बड़ा क्रेडिट उनका भी है। उन्होंने लगातार लाल सलाम को खत्म पर न सिर्फ अपना संकल्प व्यक्त किया। बल्कि सुरक्षाबलों को छूट देने के साथ उन्हें हर तरह का समर्थन दिया। पिछली बार जब नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली थी तब गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में ही नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा था। अब मार्च 2026 तक खत्म करने की योजना है।

पाकिस्तान में जहां भी होंगे आतंकी उन्हें वहीं मारेंगे

● एस जयशंकर ने चेताया, कहा-चरमपंथी है असीम मुनीर

नई दिल्ली (एजेंसी)। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर भारत के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी सेना के मुखिया असीम मुनीर को कट्टरपंथी सोच वाला इंसान बताया है। साथ ही पाकिस्तान की खुली चेतावनी देते हुए एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकवादी जहां भी छिपे होंगे, उन्हें वहीं मारा जाएगा। जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा, ऑपरेशन जारी है क्योंकि उस ऑपरेशन में एक स्पष्ट संदेश है कि अगर 22 अप्रैल को हमने जिस तरह की हरकतें देखीं अगर वैसी हरकतें दोबारा होती हैं तो जवाब दिया जाएगा। हम आतंकवादियों पर हमला करेंगे। भारतीय अधिकारियों ने पहले कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, आतंकवादी पाकिस्तान के जिस भी कोने में हैं, हम उन्हें वहीं मारेंगे। ऑपरेशन जारी रखने का एक संदेश है। ऑपरेशन जारी रखना एक-दूसरे

पर गोलीबारी करने जैसा नहीं है। अभी लड़ाई और सैन्य कार्रवाई पर सहमति बनी है। जयशंकर ने डच की मीडिया एजेंसी एनओएस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि यह हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किया गया था और इसके पीछे धार्मिक आधार पर टारगेट किलिंग की मंशा थी। जयशंकर ने कहा, हमारे पास स्पष्ट प्रमाण हैं कि पाहलगाम में जो 26 नागरिक मारे गए उन्हें हिंदू होने की वजह से निशाना बनाया गया। यह नृशंस हमला दर्शाता है कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद किस हद तक धार्मिक उन्माद से प्रेरित हो चुका है। उन्होंने कहा, उनकी आस्था का पता लगाने के बाद 26 लोगों की उनके परिवारों के सामने हत्या कर दी गई। धार्मिक मतभेद पैदा करने के लिए जानबूझकर धर्म का तत्व शामिल किया गया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान का नेतृत्व, विशेष रूप से सेना, आज चरमपंथी धार्मिक सोच से प्रेरित है।

वह केवल क्षेत्रीय शांति के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी खतरा बन चुका है। विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत इस तरह की बर्बरता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा और जवाबी कार्रवाई की रणनीति सटीक, निर्णायक और न्यायपूर्ण रहेगी।

ऑपरेशन सिंदूर पर भारत को मिला जापान का साथ

टोक्यो (एजेंसी)। जापान की राजधानी टोक्यो में भारतीय सांसदों के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से भेंट की। इस मुलाकात के दौरान भारत के दृढ़ और स्पष्ट रुख को दोहराया गया कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और इसे जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए। जापानी मंत्री ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का न केवल समर्थन किया बल्कि हालिया पहलगाम आतंकी हमले पर गहरा शोक भी व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद संजय कुमार झा ने कहा, हमने भारत का पक्ष बहुत दृढ़ता से रखा।

अब एक ही जिले में ड्यूटी कर सकेंगे हसबैंड और वाइफ

लखनऊ (एजेंसी)। पुलिस की नौकरी कितनी चुनौतियों से भरी है, इसके बारे में हर कोई जानता है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने सैकड़ों पुलिसकर्मियों को राहत भरी खबर दी है। पुलिस विभाग में कार्यरत पति और पत्नी को अब एक ही जिले में तैनात किया जाएगा। डीजीपी ने बुधवार को इस संबंध में

महत्वपूर्ण आदेश दिया है। इस आदेश के अनुसार, जिन पुलिसकर्मियों के पति या पत्नी भी पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, उन्हें अब एक ही जिले में तैनाती दी जा सकती है। यह फैसला अनुकंपा नीति के तहत लिया गया है। इसका मकसद पुलिसकर्मियों के पारिवारिक जीवन को सरल बनाना है। इस आदेश के अनुसार, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें एक ही जिले में समायोजित किया जाएगा।

पारा 40 डिग्री पार होते ही अकाउंट में आएंगे 300 रुपए

● बिहार की 1.5 लाख महिलाओं को मिलेगी अब यह सुविधा ● पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर सहित 8 जिलों से होगी शुरुआत

पटना (एजेंसी)। जेठ की आग उगलती गर्मी में काम करने वाली महिलाओं को अब अपने काम के अलावा 300 रुपए अलग से दिए जाएंगे। जिस-जिस दिन पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार करेगा उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए शर्त बस इतनी है कि इन्हें हीट वेव इंश्योरेंस कराना होगा। बिहार में पहली बार इस योजना की शुरुआत हो रही है। इसकी पहल ट्रेड यूनियन संगठन सेल्फ एप्लायड वीमेन एसोसिएशन- की तरफ से की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना की शुरुआत राज्य के 8 जिलों पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया और सीवान से किया जा रहा है। यहां दिहाड़ी मजदूरी करने वाली लगभग डेढ़ लाख महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। एजेंसी से जुड़ी अधिकारियों की मानें तो इस इंश्योरेंस का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं को लाभ पहुंचाना है।

हरियाणा में ढाई साल बाद कोरोना वायरस की एंट्री

● गुरुग्राम और फरीदाबाद में सामने आए केस, मुंबई से लौटी थी महिला, स्वास्थ्य टीमें तैनात

फरीदाबाद/गुरुग्राम (एजेंसी)। हरियाणा में करीब ढाई साल बाद फिर से कोरोना वायरस की एंट्री हुई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोविड के ये मामले सामने आए हैं। सभी कोरोना संक्रमित को होम आइसोलेट कर दिया गया है, साथ ही उनके परिवार के सभी सदस्यों के भी सैंपल लिए गए है। संक्रमित के परिजनों से संपर्क कर उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। दो मरीज गुरुग्राम से हैं, जिनमें एक महिला हाल ही में मुंबई घूमकर आई थी और दूसरा एक बुजुर्ग है, जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। फरीदाबाद का 28 वर्षीय युवक दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, उसे बुखार, खांसी और सर्दी-जुकाम की शिकायत थी। उसे इलाज के लिए दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि, ये तीनों लोग कोरोना के किस वेरिएंट के शिकार हुए हैं, इसकी पुष्टि डॉक्टरों ने अभी तक नहीं की है।

ईडी ने सारी हदें पार कीं, देश के संघीय ढांचे का किया उल्लंघन

● सुप्रीम कोर्ट बोला, तमिलनाडु शराब घोटाले की जांच पर रोक के निर्देश

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सारी हदें पार कर दी हैं। वह देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। कोर्ट ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन और तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। ईडी ने मार्च में टीएसएमसी मुख्यालय पर छापेमारी के बाद कहा था कि उसे एक हजार करोड़ रुपए की हेराफेरी का पता चला है। कॉर्पोरेट पोस्टिंग, ट्रांसपोर्ट और बार लाइसेंस टेंडर से जुड़ा डेटा मिला है। धोखाधड़ी करके शराब को तय कीमत से ज्यादा पर बेचने के भी सबूत हैं। अदालत ने एजेंसी को जांच और छापेमारी रोकने का भी निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच कर रही थी। सीजेआई बोले- निगम के खिलाफ मामला नहीं दर्ज कर सकते तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य ने 2014 से 2021 के दौरान भ्रष्टाचार मामले में शराब दुकानदारों पर 41 एफआईआर दर्ज कीं। ईडी ने 2025 में टीएसएमसी मुख्यालय पर छापा मारा। उसने अधिकारियों के फोन और डिवाइस ले गए और सब कुछ क्लोन किया। इस पर सीजेआई ने ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा

कि टीएसएमसी के खिलाफ अपराध कैसे बनाया गया। आप व्यक्तियों के खिलाफ तो आपराधिक मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन निगम के खिलाफ नहीं। आपकी ईडी सारी हदें पार कर रही है। टीएसएमसी की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा फोन की क्लोन कॉपी ले ली है।

भाखड़ा डैम पर सीआईएसएफ की तैनाती से बढ़ गया विवाद

चंडीगढ़ (एजेंसी)। भाखड़ा बांध की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा सीआईएसएफ की तैनाती पर बवाल मच गया है। पंजाब सरकार ने इसका सीधा विरोध किया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का कहना है कि जो काम पंजाब पुलिस मुफ्त में कर रही है, उसके लिए हम पैसे क्यों दें। इसकी क्या जरूरत है। मान ने कहा कि अब पानी की कोई समस्या नहीं है। यह अगले साल की तैयारी है। उन्होंने पंजाब भाजपा के बड़े नेताओं कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, रवनीत सिंह बिट्टू और मनप्रीत सिंह बादल से पूछा है कि क्या यह पत्र आपकी सहमति से जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि कल हरियाणा को उसके हिस्से का पानी जारी कर दिया गया। उसके बाद केंद्र सरकार ने फिर पंजाब पर हमला किया है। आदेश जारी किए गए हैं कि सीआईएसएफ के 296 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। प्रत्येक कर्मचारी पर प्रति वर्ष 2.90 लाख रुपये का खर्च आएगा। इस हिसाब से बीबीएमबी या पंजाब केंद्र को 8.58 करोड़ रुपये देगा। उन्होंने कहा कि इसकी क्या जरूरत थी।

कांग्रेस बोली-पहलगाम के आतंकी पहले भी हमला कर चुके

● हमलावर जम्मू-कश्मीर में घूम रहे, हमारे सांसद दुनियाभर में

नई दिल्ली/श्रीनगर (एजेंसी)। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को एक महीना हो चुका है। 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। हालांकि इस हमले में शामिल आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा- सरकार की प्राथमिकता आतंकवादियों को पकड़ने की होनी चाहिए न कि सांसदों को दूसरे देशों में भेजने की। आतंकी अभी भी जम्मू-कश्मीर में घूम रहे हैं और हमारे सभी सांसद दुनिया भर में। जयराम ने कहा कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि पहलगाम हमले के आतंकवादी पिछले 18 महीनों में तीन अन्य आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी को ''चुप्पी'' साधने के बजाय संसद का विशेष सत्र बुलाकर सदन के पटल पर स्पष्टीकरण देना चाहिए तथा सभी दलों के नेताओं से भी बातचीत करनी चाहिए।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि सांसदों के प्रतिनिधिमंडलों को विभिन्न देशों के दौरे पर भेजना 'दिखावे की निरर्थक कवायद' है और फिलहाल यह जरूरी है कि पहलगाम

हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' को रोके जाने से जुड़े सवालों का सरकार जवाब दे तथा संसद से एक सामूहिक संकल्प दुनिया के सामने रखा जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक फिर यह दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव को व्यापार समझौते के जरिए सुलझाया है। उन्होंने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान यह दावा किया। रमेश ने कहा, ''हमारे प्रधानमंत्री अपने करीबी दोस्त द्वारा बार-बार किए जा रहे इन दावों पर पूरी तरह मौन हैं।

भोपाल में पीएम सुरक्षा में तैनात रहेंगे 3 हजार जवान

आउटर नाके सील, होटल, लॉज और बाहरी किराएदारों का वेरिफिकेशन शुरू

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आएंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर जंबूरी मैदान में महिला सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब एक लाख महिलाएं शामिल होंगी। पीएम के संभावित दौरे को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम चॉक चौबंद कर दिए हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर हरीनारायणचारी मिश्रा ने तमाम आला अधिकारियों की गुरुवार को मीटिंग ली।

इस मीटिंग में पीएम की सुरक्षा से जुड़े अहम निर्देश पुलिस कमिश्नर ने अधीनस्थ अधिकारियों को दिए हैं। वहीं शहर के सभी आउटर नाकों को सील कर दिया गया है। चैकिंग के बाद ही बाहरी वाहनों को शहर की

सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। इसी के साथ भोपाल की सभी होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

महिलाएं संभालेंगी सभी जिम्मेदारी

भोपाल में रहने वाले बाहरी व्यक्तियों और किराएदारों का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है। पीएम के आगमन के दिन भोपाल में करीब 3 हजार अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात रहेंगे। सम्मेलन की खास बात यह होगी कि पूरी व्यवस्था महिलाओं के हाथों में होगी। मंच संचालन से लेकर भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक, मीडिया और सुरक्षा तक का जिम्मा महिलाएं ही संभालेंगी।

सम्मेलन में क्या-क्या होगा

- राज्य में महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं और उपलब्धियों की झलक सम्मेलन में दिखाई जाएगी।
- स्व सहायता समूहों की ओर से स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें महिलाओं के स्टार्टअप, उद्योग, नवाचार और सेव सिटी प्रोजेक्ट जैसी पहल दिखाई जाएंगी।
- महिलाओं के आने-जाने, बैठने, पानी और खाने-पीने की भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी।

इंदौर मेट्रो को दिखा सकते हैं हरी झंडी

पीएम मोदी इंदौर मेट्रो को वर्चुअली हरी झंडी दिखा सकते हैं। इंदौर में प्रायोरिटी कॉरिडोर पर गांधी नगर से स्टेशन नंबर 3 के बीच फिलहाल मेट्रो चलाई जाएगी। हालांकि इंदौर में मेट्रो के कॉमर्शियल रन की तारीख अभी तय नहीं हुई है।

एसपीजी के हाथ में होगी सुरक्षा व्यवस्था की कमान

एसपीजी की टीम ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल को अपने सुरक्षा घेरे में ले लेगी। एसपीजी के अधिकारी स्टेट हैंगर पर भी तैनात रहेंगे। इमरजेंसी हालात में पीएम को निकालने के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी रहेगी।

आदेश के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

भोपाल नगरीय पुलिस पीएम के कार्यक्रम स्थल के पांच किलोमीटर परिधि में ड्रोन, हॉट एयर बॅलून व फ्लाईंग ऑब्जेक्ट उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाली है। अगर कोई एसपीजी की बिना अनुमति ऐसा करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

केवीआईसी के 'हनी मिशन' में 20 हजार मीट्रिक टन शहद का हुआ उत्पादन

मधुमक्खी पालकों को 325 करोड़ रुपये की हुई आमदनी

भोपाल (नप्र)। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने 'विश्व मधुमक्खी दिवस-2025' के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस वर्ष का आयोजन थीम 'प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खी, सबके जीवन की पोषक' पर आधारित था, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण 'श्वेत क्रांति से स्वीट क्रांति' के अभियान को सशक्त करता है। इसमें महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से आए मधुमक्खी पालक लाभार्थी, प्रशिक्षु, वैज्ञानिकों, सफल मधुमक्खी पालकों, विद्यार्थियों और विशेषज्ञों की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में केवीआईसी की उपलब्धियों को साझा किया गया। यह आयोजन न केवल एक तकनीकी मंच रहा, बल्कि ग्रामीण भारत के नवाचार, प्रेरणा और स्वावलंबन की सजीव मिसाल बना। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि केवीआईसी अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुश्री रूप राशि की उपस्थिति में किया।

देश में 'हनी मिशन' में 2,29,409 मधुमक्खी बक्से और मधु कॉलोनियां की गई वितरित

केवीआईसी अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने मधुमक्खी दिवस पर आयोजित समारोह में कहा कि मधुमक्खियां हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं। ये न केवल शहद देती हैं, बल्कि परागण के जरिए हमारी खेती को समृद्ध करती हैं और पर्यावरण का संरक्षण करती हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया 'हनी मिशन' आज गांवों की आजीविका का बड़ा आधार बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जब 'स्वीट क्रांति' का आह्वान किया, तब उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया, जिसमें शहद उत्पादन न केवल आर्थिक समृद्धि का, बल्कि स्वास्थ्य समृद्धि का भी स्रोत बना। उनके नेतृत्व में केवीआईसी ने इस दिशा में जो कार्य किया है, वह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है।

केवीआईसी अध्यक्ष ने 'हनी मिशन' की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि केवीआईसी द्वारा अब तक देशभर में 2,29,409 मधुमक्खी बक्से और मधु कॉलोनियां वितरित की गई हैं। इससे लगभग 20,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ है। मधुमक्खी पालकों को इससे लगभग 325 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में हनी मिशन से जुड़े मधुमक्खी पालकों ने करीब 25 करोड़ रुपये मूल्य का शहद विदेश में भी निर्यात किया है।

केवीआईसी की सीईओ सुश्री रूप राशि ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हनी मिशन केवल एक योजना नहीं, बल्कि यह एक समग्र आजीविका मॉडल है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों युवाओं, महिलाओं और किसानों को इस मिशन से रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केवीआईसी द्वारा संचालित हनी प्रोसेसिंग प्लांट्स, प्रशिक्षण केंद्र और मार्केटिंग नेटवर्क ने मधुमक्खी पालन को आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर किया है।

कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने बताया कि मधुमक्खियां केवल शहद उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लगभग 75 प्रतिशत खाद्य फसलों का परागण मधुमक्खियों से होता है। मधुमक्खियां यदि न रहें, तो 30 प्रतिशत खाद्य फसलें और 90 प्रतिशत जंगली पौधों की प्रजातियां संकट में आ सकती हैं। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश सहित देश के सभी हिस्सों से लाभार्थियों ने डिजिटल रूप से अपनी सफलता की कहानियां साझा कीं। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुत नाटक, कविता, और निबंध ने कार्यक्रम में जीवंत कर दिया। कार्यक्रम में केवीआईसी के अधिकारी, कर्मचारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

जैव विविधता का संरक्षण जीवन के लिये महत्वपूर्ण : अहिरवार

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर कार्यशाला एवं संगोष्ठी हुई

भोपाल (नप्र)। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री दिलीप सिंह अहिरवार ने कहा कि जैव विविधता का संरक्षण हमारे जीवन के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमें जैव विविधता के महत्व को समझने और उसके संरक्षण के लिये प्रयास करने होंगे। मंत्री श्री अहिरवार नरोन्हा प्रशासन अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण के लिये सरकार के साथ मिलकर समाज को भी काम करना होगा।

राज्य मंत्री श्री अहिरवार ने कहा कि वन विभाग द्वारा संघर्ष एवं चुनौती के साथ प्रकृति और पेड़-पौधों को संरक्षित करने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पथरीली जमीन पर भी कठिन परिश्रम से पौधे लगाकर वन तैयार करने का प्रशंसनिय कार्य वन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में विलुप्त हो रहे जीवों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में विलुप्त हो रहे किंग कोबरा को वन विहार में बेंगलुरू (कर्नाटक) से लाया गया है। वन विभाग गिद्ध, घड़ियाल और मगरमच्छ के भी संरक्षण का कार्य कर रहा है। मंत्री श्री अहिरवार ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

मंत्री श्री अहिरवार ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर राज्य स्तरीय वार्षिक जैव विविधता पुरस्कार, राज्य स्तरीय वार्षिक जैव विविधता पुरस्कार 2023-24 और मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय जैव विविधता क्विज प्रतियोगिता के पुरस्कारों का वितरण किया। उन्होंने इस अवसर पर जैव विविधता पर आधारित पोस्टर का विमोचन भी किया। मंत्री श्री अहिरवार ने कार्यक्रम स्थल पर जैव विविधता वनस्पति स्टॉल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मंत्री श्री अहिरवार ने कार्यक्रम में जैव विविधता आधारित नुक्कड़ नाटक भी देखा।

अपर मुख्य सचिव वन श्री अशोक वर्णवाल ने कहा कि जैव विविधता दिवस का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उसके महत्व को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत् विकास है, जो हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाने और उसके संरक्षण के लिये प्रेरित करती है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री असीम श्रीवास्तव ने कहा कि वन विभाग द्वारा जैव विविधता के क्षेत्र में कई नवाचार किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा जंगलों के संरक्षण का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वनस्पति और जीव-जंतुओं का संरक्षण जैव विविधता के संरक्षण के लिये महत्वपूर्ण है। वन बल प्रमुख श्री श्रीवास्तव ने कहा कि वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, जिससे वन क्षेत्र में वृद्धि होगी और जैव विविधता का संरक्षण होगा। मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड श्री सुदीप सिंह ने जैव विविधता बोर्ड द्वारा की जा रही उपलब्धियों की जानकारी कार्यशाला में साझा की। उन्होंने कहा कि जैव विविधता बोर्ड द्वारा नये अभियान चलाकर जैव विविधता का संरक्षण का किया जा रहा है।

अमृत रेलवे स्टेशनों के उद्घाटन में राज्यपाल वर्चुअली हुए शामिल

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने

विरासत और विकास के प्रतीक देश के पुनर्विकसित 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का राजस्थान के बीकानेर में उद्घाटन किया। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल राजभवन से बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। समारोह में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 26 हजार करोड़ रूपये के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया।

इस अवसर पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री के.सी. गुप्ता, राज्यपाल के अपर सचिव श्री उमा शंकर भार्गव, जनजाति प्रकोष्ठ राजभवन की सदस्य सचिव श्रीमती जमुना भिड़े सहित राजभवन के अधिकारी गण उपस्थित थे।

उपराष्ट्रपति धनखड़ नरसिंहपुर में 26 मई को करेंगे कृषि उद्योग समागम का शुभारंभ

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इन्वेस्ट मध्यप्रदेश के अंतर्गत अनंत संभावनाओं के दृष्टिगत नरसिंहपुर में 26 मई को कृषि उद्योग समागम का आयोजन होगा। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ समागम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित मंत्रीगण, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, उद्योगपति, किसान, आमजन आदि मौजूद रहेंगे।

कार्यक्रम का उद्देश्य- कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन मध्यप्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, खाद्य प्रसंस्करण में निवेश आकर्षित करने, और किसानों को बेहतर बाजार से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। यह समागम उद्योगपतियों कृषक उत्पादक संगठनों एवं नीति निर्माताओं के बीच संवाद, नीति प्रस्तुति एवं सहयोग के अवसर प्रदान करेगा। कार्यक्रम में उद्योग इकाइयों का शिलान्यास एवं लोकार्पण तथा उद्योगपतियों को भूमि आवंटन पत्र एवं आशय पत्रों का वितरण भी होगा।

राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में हरसंभव प्रयास कर रही है। मध्यप्रदेश का किसान सम्पन्न होगा तो प्रदेश और देश भी समृद्ध होगा। राज्य सरकार युवा, महिला और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि उद्योग समागम में आधुनिक कृषि तकनीकों व उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। समागम में कृषि के साथ खाद्य प्र-संस्करण, उद्यानिकी और पशुपालन से संबंधित जानकारी मिलेगी।

बाइक से गिरा किसान, ट्रक की चपेट में आया, मौत

भोपाल (नप्र)। बैरसिया इलाके में एक किसान की बाइक स्लिप हो गई। सड़क पर गिरते ही पीछे से आ रहे ट्रक ने किसान को चपेट में ले लिया। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जहां इलाज के दौरान गुरुवार तड़के उसकी मौत हो गई। जबकि हादसा बुधवार देर रात का है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

थाना प्रभारी अरूण मिश्रा के मुताबिक खेती-किसानी करने वाला 40 वर्षीय रामलखन दांगी बरखेड़ा बरामद में रहते थे। बुधवार देर रात वह अपनी बाइक से गांव स्थित घर जा रहे थे। तभी रास्ते में पेट्रोल पंप के पास उनकी बाइक बेकाबू होकर स्लिप हो गई। जिससे वह सड़क पर गिर गए, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। ट्रक का चालक फरार हो गया।

अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस- अस्पताल की सूचना के बाद पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए रवाना किया। जिसकी बॉन बॉडी पीएम के लिए मर्चुरी भेज दी गई। गुरुवार की दोपहर को पीएम के बाद बॉडी को परिजनों के हवाले कर दिया गया है।

छतरपुर में करंट लगने से महिला की मौत

आंधी में बिजली का तार टूटकर नीचे गिरा, गेट बंद करते समय चपेट में आई

छतरपुर (नप्र)। छतरपुर में एक महिला को करंट लग गया। गेट बंद करते समय वह चपेट में आई थी। परिवार वाले उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के अनुसार कटारेपुरवा की रहने वाली अनीता पटेल (38) की करंट लगने से मौत हुई है। ससुर लाखापति पटेल ने बताया कि बुधवार रात आंधी के चलते घर के ऊपर से गुजरा बिजली का तार टूटकर गेट पर गिर गया था। अनीता ने जैसे ही गेट बंद किया, उन्हें करंट का झटका लगा और वह नीचे गिर गई।

उन्होंने बताया कि बहू को ईसानगर अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर अनीता को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अनीता की तीन बेटी और एक बेटा है। पुलिस का कहना है कि मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार कर शव का पीएम करवाया है।

अवैध कॉलोनियों में चली जेसीबी

सिंकराबाद-खरपा में 3 कॉलोनी के गेट तोड़े, बरखेड़ी में भी कार्रवाई

भोपाल (नप्र)। भोपाल में गुरुवार को अवैध कॉलोनियों में बड़ी कार्रवाई की गई। हुजूर तहसील के सिंकराबाद-खरपा में 3 कॉलोनी के गेट जेसीबी की मदद से तोड़ दिए गए। वहीं, बरखेड़ी में भी कार्रवाई हुई।

हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया ने बताया, अवैध कॉलोनियों में किए गए निर्माण की पहले जांच की गई। जांच के बाद गुरुवार को पुलिस बल के साथ कार्रवाई की गई।

यहां हुई कार्रवाई

- ग्राम खरपा में समृद्धि फार्म पर अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई। गेट को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। सड़क, बाउंड्रीवॉल भी बना ली गई थी।
- ग्राम सिकंदराबाद में नूर खान पिता अनवर खान, आरिफ पिता पीरदास खान की भूमि अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई हुई।
- ग्राम सिकंदराबाद में अरविंदो कॉलेज के सामने उजमा इम्तियाज पति तारिक सिद्दीकी की भूमि पर विकसित हो रही अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई।
- ग्राम बरखेड़ी बाज्यफत में राधाकृष्ण परिसर एवं एचके बिल्डर्स की अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई।
- ग्राम कोड़िया में डॉ अनिल खेवानी द्वारा कुशाग्र ग्रीन फार्म्स में अवैध कॉलोनी पर विकसित की जा रही थी। यहां भी जेसीबी की मदद से निर्माण तोड़ दिए गए।ग्राम कोड़िया में शासकीय आवागमन के रास्ते पर अनधिकृत निर्माण को हटाया गया।

उज्जैन में ग्रामीणों ने की 11 आरोपियों के घर तोड़ने की मांग, हजारों वाहन फंसे थे

लव जिहाद को लेकर प्रदर्शन, 6 घंटे बंद रहा नेशनल-हाईवे

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन लव जिहाद केस में गिरफ्तार 11 आरोपियों के घर तोड़ने की मांग की जा रही है। इसे लेकर ग्रामीण सकल हिंदू समाज के साथ मिलकर कई दिनों से अलग-अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं।

गुरुवार को भी लोग सड़क पर उतर आए और उज्जैन-झालावाड़ नेशनल हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। इससे वहां वाहनों की कतारें लग गईं। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों को समझाइश देने पहुंचे। ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए उज्जैन से डिप्टी कलेक्टर कृतिका भीमावद भी वहां पहुंची।

अधिकारियों की काफी समझाइश के बाद प्रदर्शनकारी माने। 6 घंटे बाद चक्काजाम खुल सका। अधिकारियों ने ग्रामीणों को नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

तेज धूप होने के कारण ग्रामीणों ने बीच सड़क पर टेंट लगा लिया था। बातचीत का हल नहीं निकलने की सूरत में ग्रामीण रात भर डटे रहने की बात कर रहे थे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं, झालावाड़ जाने वाले मार्ग को गरोठ की ओर डायवर्ट किया गया है।

बता दें, बिछड़ोद गांव में 6 मई को लव जिहाद का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने अश्लील फोटो-वीडियो और चैट के जरिए हिंदू लड़कियों को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

नेशनल हाईवे पर लगी थीं वाहनों की कतारें

जुलूस के बाद भी ग्रामीणों की मांग थी कि आरोपियों के मकान तोड़े जाएं। पिछले हफ्ते सकल हिंदू समाज के साथ ग्रामीणों ने बिछड़ोद बंद रखा। मांगें न माने जाने पर गुरुवार को नजरपुर में उज्जैन-झालावाड़ नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया था। 5 घंटे चले चक्काजाम के चलते मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी।

अफसर बोले- एससी गाइडलाइन के तहत कार्रवाई- हालात को संभालने के लिए एसडीएम राजाराम करजरे, सीएसपी भारत सिंह यादव, तहसीलदार जीवन मोघी सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एसडीएम ने ग्रामीणों को समझाया कि अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।

मुस्लिम युवक के साथ वीडियो वायरल हुआ था- दरअसल, 6 मई को बिछड़ोद गांव की एक लड़की का मुस्लिम युवक के साथ वीडियो वायरल हुआ था, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने फरमान नाम के युवक और एक अन्य को पकड़कर उनके मोबाइल की जांच की, जिसमें गांव की लड़कियों के अश्लील फोटो-वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग मिली।

इसके बाद ग्रामीणों ने फरमान को घट्टिया थाना पुलिस के हवाले कर दिया और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इसके विरोध में गांव पूरी तरह बंद रखा। इस दौरान हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। गुस्साए ग्रामीणों ने मुख्य आरोपी के घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। बाद में पुलिस ने सभी आरोपियों का जुलूस निकाला।

वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म

पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर कई बार गलत काम किया था। 7 लड़कों की गैंग पिछले डेढ़ साल से टारगेट करके लड़कियों को चुनती थी। मुख्य आरोपी फरमान लड़कियों के संपर्क में रहता था। इसी ने 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था।

नाबालिग पीड़िता बोली- धमकाकर रेप किया

14 वर्ष की पीड़िता ने पुलिस को बताया- 30 मार्च 2025 को ईद के दिन फरमान मंसूरी ने सुनसान जगह पर मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया। फिर गले लगा लिया। उसके दोस्त जुबैर ने मोबाइल में फोटो ले लिए और वहां से चला गया।

इसके बाद फरमान मुझे धमकाकर मंडी के गेट के पास एक कमरे में ले गया। यहां मेरे साथ बलात्कार किया। फिर बोला- यदि तू मेरे से बात नहीं करेगी या मेरे बारे में किसी को बताएगी तो हम दोनों की फोटो वायरल कर दूंगा।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रीवा पहुंचे

तीन दिन संगठन को लेकर करेंगे मंथन, एसपी सहित 300 जवान सुरक्षा में तैनात

रीवा (नप्र)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत गुरुवार को तीन दिवसीय दौरे पर रीवा पहुंचे। भागवत दोपहर 12 बजे बेला से सड़क मार्ग होते हुए शहर पहुंचे। वह यहां संगठनात्मक रणनीतियों की समीक्षा और उन्हें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आए है।

प्रवास के दौरान भागवत वरिष्ठ आरएसएस सदस्यों से मिलेंगे, रणनीति चर्चाओं में भाग लेंगे और स्वयंसेवकों

से बातचीत करेंगे। उनके कार्यक्रम में आरएसएस की शाखाओं का दौरा, जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सत्र और राज्य भर में संघ की गतिविधियों की समीक्षा शामिल है।

एसपी सहित 300 जवान सुरक्षा में तैनात- जेड-प्लस सुरक्षा प्राप्त आरएसएस प्रमुख की सुरक्षा में दो सीएसपी, एडिशनल एसपी और एसपी विवेक सिंह खुद तैनात हैं। शहर भर में सभी थानों के लगभग 300 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है। निराला नगर स्थित सरस्वती विद्यालय और बैठक स्थल पर संघ कार्यकर्ताओं के अलावा किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है।

संपादकीय

नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता

छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच चली 72 घंटे की मुठभेड़ में शीर्ष माओवादी नेता बसवराज समेत 27 नक्सलियों का मारा जाना हमारे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता है। हालांकि इसमें एक जवान भी शहीद हुआ। यह मुठभेड़ उस नक्सल विरोधी अभियान के बाद हुई है, जो छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ियों में 21 दिन चला था। इसमें 31 माओवादी मारे गए थे और उनके बड़े नेताओं को बड़ा झटका लगा था तथा अब यह दूसरा बड़ा झटका है। सुरक्षा बलों की इस कामयाबी की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। वैसे भी सुरक्षा बल नक्सलियो के खिलाफ सभी नक्सल प्रभावित राज्यों में जिस तरह से सघन अभियान चला रहे हैं, उससे यही लगता है कि केन्द्रीय गृहमंत्री द्वारा नक्सलियों के सफाए की 31 मार्च 2026 की डेडलाइन अब ज्यादा दूर नहीं है। सरकार की सख्त नीति और नक्सलियों पर सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के चलते देश में नक्सलवाद अब चार राज्यों के 6 जिलों तक सिमट गया है। इसका मुख्यं कारण यह है कि नक्सलियों की हिंसक कार्यशैली से आम लोग अब उकता चुके हैं। वो शांति चाहते हैं। दूसरे, देश में नक्सल आंदोलन तो साठ साल से चल रहा है, लेकिन नक्सली शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए सशस्त्र क्रांति के अपने लक्ष्य को तनिक भी नहीं पा सके हैं। वो जिस लाइन पर चल रहे हैं, वह मूलतः चीनी कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की लाइन है, जिसे खुद चीन भी पीछे छोड़ चुका है। दुनिया अब काफी बदल चुकी है। अब तो सशस्त्र लड़ाइयों की जगह संसाधनों पर कब्जे के लिए अंतरराष्ट्रीय संघर्ष शुरू हो चुका है। लेकिन खुद को माओंवादी कहलाने वाले नक्सली अभी भी उसी बाबा आदम के जमाने में जी रहे हैं। नक्सल आंदोलन वहां भी दम तोड़ चुका है, जहां से यानी पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से यह शुरू हुआ था। समाज और राजनीतिक व्यवस्था को आमूलचूल बदल डालने की जिद में शुरू हुआ यह आंदोलन अब रंगदारी वसूलने, दूरदराज के क्षेत्रों में गरीब आदिवासियो को मारने और अपना धंधा चलाने में तब्दील हो चुका है। इसे चलाने वाले चंद अर्बन नक्सल हैं, जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। नक्सलियों के पास अवैध हथियारों का जखीरा है और वो सुरक्षा बलों को मारने में अपनी बहादुरी समझते हैं। जबकि हकीकत यह है कि देश में उनका समर्थन लगातार घटता जा रहा है। उधर सरकार नक्सलियों को मार ही नहीं रही है, वह आत्म समर्पण करने वाले नक्सलियों का समुचित पुनर्वास भी कर रही है। यह भी कारण है कि बहुत से नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यह धारा में लौट रहे हैं और शांतिपूर्वक अपना जीवन बिता रहे हैं। इनमें से कई तो सुरक्षा बलों में भर्ती होकर नक्सलियों को मारने में मदद भी कर रहे हैं। नक्सलियों पर यह शिकंजा सुरक्षा बलों की नई रणनीति कि नक्सलियों को उनके घर में घुस कर मारेंगे, के कारण ज्यादा कसा गया है। करैंगुट्टा की पहाड़ी नक्सलियों की सुदूर इलाके में स्थित सुरक्षित पनाहगाह थी। लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे भी खोज निकाला और वहां रह रहे नक्सलियों को ठिकाने लगा दिया। जहां तक मप्र की बात है तो यहां केवल छत्तीसगढ़ से लगे जिलों के सीमावर्ती इलाकों नक्सली गतिविधियां देखी गई हैं। लेकिन यहां भी सरकार सख्ति है। कई लोग नक्सलवाद को सामाजिक समस्या मानते हैं, वह है भी,लेकिन जिस तरह नक्सली भारतीय संविधान को ठुकरा कर अपना राज कायम करना चाहते हैं, वह किसी भी भारतीय नागरिक को स्वीकार्य नहीं होगा। नक्सली समस्या का स्थायी समाधान उन समस्याओं का निदान है, जिनके कारण नक्सलवाद पनपा।

मार्च 2026 के पहले नक्सलवाद का खात्मा संभव

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चल रहा अभियान बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा है। इसमें 21 मई 2025 को नक्सली इतिहास के पन्ने में नक्सली सफाई का एक ऐसा अध्याय लिख दिया गया है, जो अब नक्सलियों की सफाई की अंतिम कहानी को लिखेगा। साल 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी की कोख से जन्मे नक्सलवाद और उसकी लड़ाई में पहली बार ऐसा हुआ है, जब नक्सलियों के महासचिव की टीम से सीधी टक्कर हुई है जिसमें उनका शीर्ष कमांडर मारा गया हो। इससे पहले महासचिव स्तर के कमांडर नीतियां बनाते थे। लड़ाई पहले लेयर के नक्सली लड़ते थे लेकिन अब शायद वह लेयर भी खत्म हो गई है, जो सुरक्षा बलों के चलाए जा रहे अभियान की सबसे बड़ी कामयाबी है।

नजरिया

अशोक भाटिया
लेखक मुंबई निवासी स्वतंत्र पत्रकार हैं।

नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में सीपीआई माओवादी के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू सहित 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चल रहा अभियान बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा है। इसमें 21 मई 2025 को नक्सली इतिहास के पन्ने में नक्सली सफाई का एक ऐसा अध्याय लिख दिया गया है, जो अब नक्सलियों की सफाई की अंतिम कहानी को लिखेगा। साल 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी की कोख से जन्मे नक्सलवाद और उसकी लड़ाई में पहली बार ऐसा हुआ है, जब नक्सलियों के महासचिव की टीम से सीधी टक्कर हुई है जिसमें उनका शीर्ष कमांडर मारा गया हो। इससे पहले महासचिव स्तर के कमांडर नीतियां बनाते थे। लड़ाई पहले लेयर के नक्सली लड़ते थे लेकिन अब शायद वह लेयर भी खत्म हो गई है, जो सुरक्षा बलों के चलाए जा रहे अभियान की सबसे बड़ी कामयाबी है।

बताया जाता है कि नक्सलियों के लिए मई और जून का महीना उनके हिसाब-किताब का महीना होता है। नक्सलियों के हिसाब किताब के महीने से तात्पर्य सिर्फ इस बात का नहीं है कि नक्सलियों को कितनी लेवी आई है या नक्सली कितना पैसा वसूले हैं। हिसाब किताब का महीना इसलिए इसे कहा जाता है कि नक्सली चाहे दवा का भंडारण हो या फिर खाने का सामान या बंदूक की जरूरत हो या फिर गोलियों की यह सभी हिसाब किताब मई और जून महीने में कर लेते हैं। इस सफलता के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि जंगल में जहां नक्सली रहते हैं, उसके आसपास छोटी बड़ी नदियां होती हैं। मई और जून के महीने में इन नदियों में पानी नहीं होता है। जिसके कारण परिवहन बहुत आसान होता है। खाने पीने का सामान, दवाई या उससे जुड़ी चीजें आसानी से बाजार से लेकर जंगल में उनके ठिकाने तक पहुंचाई जाती हैं। बारिश का महीना होने के बाद नदियों में पानी आ जाता है। फिर नदी पार करके इन सामानों को लाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस महीने में इनके भंडारण का सबसे ज्यादा काम होता है। इस बार इसी हिसाब किताब के महीने पर सुरक्षा एजेंसियों ने सबसे ज्यादा पहरा बैठा दिया है। जिसका परिणाम है कि अब नक्सलियों के महासचिव स्तर के कमांडर मारे जा रहे हैं।

इस ऑपरेशन मारे गए नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू भी सीपीआई-माओवादी का महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस बड़ी सफलता के लिए वे हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करते हैं। यह भी खुशी की बात है कि ऑपरेशन ब्लैक

फॉरेस्ट के पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।

बाला केशव राव उर्फ बसवराजू पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। आंध्र प्रदेश,तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी उस पर अलग-अलग इनाम घोषित थे। उसकी गिनती उन चुनिंदा नक्सल नेताओं में होती थी जो पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति दोनों सर्वोच्च निकायों में शामिल था। उसे एक ऐसा नक्सल नेता माना जाता था जो जंगल में अपनी तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और नेटवर्क के कारण कभी भी पकड़ा नहीं गया। बसवराजू का जन्म आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जियान्नापेटा गांव में हुआ था।उसने वारंगल के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया था। लेकिन पढ़ाई के बाद उसने बंदूक उठा लिया। साल 1970 के दशक में उसने नक्सली आंदोलन से जुड़कर प्रकाश, कृष्णा, विजय, उमेश और कमलू जैसे कई छद्म नामों से काम करना शुरू कर दिया। वो शुरू में जमीनी कार्यकर्ता था, लेकिन जल्द ही संगठन की रणनीति औरहथियारों की ट्रेनिंग में माहिर हो गया।साल 1992 में उसे पीपुल्स वार ग्रुप की केंद्रीय समिति का सदस्य बनाया गया। उस वक्त इस ग्रुप का महासचिव गणपति हुआ करता था। बसवराजू को गणपति और सीतारामैयाजैसे नेताओं से गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण मिला। उसने धीरे-धीरे सैन्य रणनीति, आईडी और बारूदी सुरंगों के संचालन में महारत हासिल कर लिया। साल 2018 में बसवराजू को सीपीआई (माओवादी) का महासचिव नियुक्त किया गया। उसने गणपति की जगह ली, जिसने उम्र और बीमारी के चलते पद छोड़ दिया था। लेकिन बसवराजू की कमजोरी यह रही कि उसके पास संगठन को राजनीतिक रूप से चलाने का अनुभव नहीं था। इसलिए सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि उसके कार्यकाल में माओवादी आंदोलन रणनीतिक रूप से कमजोर हुआ। हालांकि वह सैन्य अभियानों के लिए जिम्मेदार रहा और बस्तर में कई बड़े हमलों की साजिश रचता रहा।

सुरक्षा विशेषज्ञ और प्रोफेसर डॉ. गिरीशकांत पांडे बताते हैं, 'बसवराजू एक सैन्य रणनीतिकार था लेकिन उसके पास राजनीतिक सोच का अभाव था। उसके नेतृत्व में माओवादी आंदोलन ने दिशा खो दी। यही वजह है कि माओवादी आंदोलन दिशा भटक गया। उसकी मौत माओवादी नेटवर्क की रीढ़ तोड़ने जैसा है।'

नक्सलियों के खिलाफ पिछले दिनों हुई कार्रवाई की मिली जानकारी के अनुसार 21 मई 2025 से पहले 21 दिनों में 31 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों के लिए हथियार बनाने वाली लेथ मशीन को जप्त किया गया है। नक्सलियों के 818 बीजीएल सेल बरामद किया गया है। 450 आईडी बम डिफ्यूज किए गए हैं। 2 साल के लिए नक्सलियों द्वारा रखा गया राशन जप्त किया गया है। बंदूक और दूसरे हथियार बनाने की दो फैक्ट्रियों को पकड़ा गया है। नक्सलियों के एक दर्जन से ज्यादा कैंप को ध्वस्त किया गया है। नक्सलियों के इलाज के लिए बनाए गए चार अस्पताल को पूरे तौर पर ध्वस्त कर दिया गया है। हथियारों का बड़ा जखीरा पुलिस ने बरामद किया है। 21 मई 2025 को महासचिव को मारकर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मनोबल को तोड़ दिया है। पिछली नक्सलवादी घटनाओं को देखें तो 2003 में अलीपीरी बम विस्फोट में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम चंद्रबाबू नायडू की हत्या का प्रयास हुआ। 2010 में दंतेवाड़ा नरसंहार में 76 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे। 2013 में झीरम घाटी हमले में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित 27 लोग मारे गए थे। 2019 में श्यामगिरी हमला में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी सहित पांच लोग मारे गए। 2020 में मिनपा एंबुश सुकमा में हुए नक्सली हमले में 17 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। 2021 में टेकलगुड़ेम जापुर में उस साल का सबसे बड़ानक्सली हमला हुआ जिसमें 22 जवान शहीद हो गए।

सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, अब नक्सल संगठन में ऐसा कोई अनुभवी नेता नहीं बचा है जो 40 से 50 वर्ष की उम्र का हो और नेतृत्व की क्षमता रखता हो। मौजूदा नेतृत्व या तो बुजुर्ग है या अनुभवहीन है। इससे नक्सली नेटवर्क के बिखराव की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ यह निर्णायक लड़ाई है। सुरक्षा बलों ने निश्चित तौर पर बड़ा काम किया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमने अपने एक सिपाही को खोया है। लेकिन उसके बाद भी सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा हुआ है। हर हाल में तय समय सीमा के भीतर हम नक्सल समस्या का समाधान छत्तीसगढ़ में करके रहेंगे। मोदी सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है।

राजनीति

नृपेन्द्र अभिषेक नृप
लेखक स्तंभकार हैं।

मित्रता के मुखौटे में स्वार्थ की राजनीति

राजनीति और व्यापार का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना सत्ता और हथियारों का। जब-जब वैश्विक व्यवस्था आर्थिक हितों के हाथों में रही है, तब-तब नैतिकता, कूटनीति और राष्ट्रवाद की परिभाषाएं परिवर्तित होती रही हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए यह चुनौती और भी विकट हो जाती है, जब वह एक ओर अपने आत्मसम्मान और संप्रभुता की रक्षा करता है और दूसरी ओर वैश्विक पूंजीवाद के दबावों का सामना करता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को लेकर दिए गए कई बयानों ने यही द्वंद्व उजागर किया, एक ओर राष्ट्रवाद का उदय, दूसरी ओर डॉलर की दरकार।

भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद एक सशक्त हथियार बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में भाजपा सरकार ने 'राष्ट्र प्रथम' की भावना को चुनावी मंच से लेकर विदेश नीति तक हर स्तर पर प्रमुखता से प्रस्तुत किया। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, धारा 370 जैसे निर्णयों को एक संगठित राष्ट्रवादी विमर्श के तहत जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। 'तिरंगा यात्रा' जैसे आयोजनों में शक्ति प्रदर्शन और राष्ट्रप्रेम की भावनाएं उभारी गईं, लेकिन ये कार्यक्रम कई बार प्रतीकात्मकता से आगे नहीं बढ़ सके। सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऐसे वीडियो, जिनमें यात्रा समाप्ति के बाद सड़क किनारे तिरंगे पड़े मिले, यह दर्शाते हैं कि राष्ट्रवाद यदि केवल उत्सव बन जाए और जीवन मूल्य न बने, तो वह खोखला रह जाता है।

इसी बीच जब भारत ने अपने आर्थिक और कूटनीतिक हितों को वैश्विक मंचों पर पुनर्परिभाषित करना शुरू किया, तब अमेरिका की ओर से आर्थिक दबाव की एक नई रणनीति उभरने लगी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान- 'भारत जितना टैक्स अमेरिका पर लगाता है, उतना अमेरिका भी भारत पर लगाएगा', केवल व्यापारिक असंतुलन का बयान नहीं था, वह भारत की आर्थिक नीतियों पर दबाव बनाने का स्पष्ट संकेत भी था। यह बात तब और गंभीर हो जाती है जब ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत में बनाए जा रहे आई फोन उत्पादन पर अप्रत्यक्ष आपत्ति जताई जाती है और टिम कुक को भारत से 'निर्माण बंद करने' की सलाह दी जाती है।

यह स्पष्ट संकेत है कि जब अमेरिका को अपने हितों की रक्षा करनी होती है, तो वह मित्रता के आवरण को उतार कर प्रतिस्पर्धा का वस्त्र धारण कर लेता है।भारत-अमेरिका संबंध कभी भी पूर्ण मित्रता पर आधारित नहीं रहे, वे हमेशा आपसी लाभ, सामरिक समीकरण और व्यापारिक संतुलन पर टिके रहे हैं। अमेरिका के लिए भारत एक बड़ा बाजार है, न कि एक समान अधिकारों वाला भागीदार। ट्रंप के बयानों ने यह बार-बार स्पष्ट किया कि जब भारत 'मेक इन इंडिया' की बात करता है, तब अमेरिका को डर सताता है कि कहीं उसकी कंपनियां भारत में सस्ती श्रमशक्ति का लाभ उठाकर प्रतिस्पर्धा में पीछे न छूट जाएं।

यह विरोधाभास उस समय और गहराता है जब अमेरिका भारत के साथ सामरिक साझेदारी की बात करता है, लेकिन उसके ही नेता पाकिस्तान को समर्थन देने वाले बयान दे देते हैं। बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद भी ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग-थलग नहीं किया। बल्कि कई अवसरों पर पाकिस्तान को 'स्ट्रेटजिक पार्टनर' कहा गया। यह दोहरा रवैया बताता है कि अमेरिका की नीति किसी आदर्श या मूल्य आधारित नहीं, बल्कि अवसरवादी और व्यापारिक रही है।

भारत के लिए यह चुनौतीपूर्ण स्थिति है। एक ओर वह आतंकवाद और राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर वैश्विक सहमति चाहता है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश व्यापारिक संतुलन और डॉलर के खेल में उलझे हुए हैं। यह स्थिति भारत को मजबूर करती है कि वह अपनी विदेश नीति को और अधिक आत्मनिर्भर तथा संतुलित बनाए। अमेरिका पर अंधानुकरण करना या केवल पश्चिम के हितों की पूर्ति करना, अब भारत जैसे उभरते राष्ट्र के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है।

हाल ही में जब ट्रंप ने ऐप्पल को भारत में निवेश रोकने का परोक्ष आदेश दिया, तो यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिकी नेतृत्व केवल आर्थिक स्वार्थों से प्रेरित होकर नीतिगत हस्तक्षेप करता है। भारत की स्वायत्तता और आर्थिक निर्णयों में इस प्रकार का हस्तक्षेप उसकी संप्रभुता पर सीधा आघात है। लेकिन भारत ने इस पर जितनी संयमित प्रतिक्रिया दी, वह कूटनीतिक परिपक्वता का परिचायक थी। भारत ने किसी भी बयान को सार्वजनिक स्तर पर नकारा नहीं, न ही उसके प्रतिरोध में तीखी प्रतिक्रिया दी। यह बताता है कि भारत अब वैश्विक राजनीति को केवल भावनाओं से नहीं, ठोस रणनीति से देख रहा है।

भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अमेरिका की इस आर्थिक रणनीति का कैसे जवाब दे? क्या वह आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को और अधिक ठोस बनाकर इस दबाव से उबर सकता है? क्या वह घरेलू उद्योगों को इतना सक्षम बना सकता है कि विदेशी निवेशकों की धमकियों से प्रभावित हुए बिना नीति निर्धारण कर सके? इन सवालों के उत्तर आज भारत को न केवल अपने भीतर ढूंढने हैं, बल्कि वैश्विक मंचों पर भी अपने आत्मविश्वास से प्रस्तुत करने हैं।

भारत को यह भी समझना होगा कि विश्व के किसी भी देश की मित्रता स्थायी नहीं होती, स्थायी होते हैं केवल स्वार्थ। सऊदी अरब, कतर, अज़रबैजान, तुर्की जैसे देशों ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, और अमेरिका ने भी तटस्थ रहकर अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर दबाव डाला। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में भारत का रुख संयमित और सधा हुआ रहा। यही वह नीति है जो एक मजबूत राष्ट्र की पहचान कराती है।

भारत अब केवल एक बाजार नहीं, एक रणनीतिक शक्ति बन चुका है। उसकी जनसंख्या, तकनीकी क्षमता, सैन्य शक्ति और आर्थिक संभावनाएं उसे वैश्विक परिदृश्य में केंद्र बिंदु बनाती हैं। ऐसे में अमेरिका हो या कोई अन्य देश, भारत को अब 'निर्देशित मित्र' नहीं, बल्कि 'समान भागीदार' मानकर संवाद करना चाहिए। यदि अमेरिका भारत को केवल टैक्स, टैरिफ और आयात-निर्यात की शर्तों में नापेगा, तो वह एक बड़ी भू-राजनीतिक भूल करेगा।

डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल भारत-अमेरिका संबंधों के लिए कई स्तरों पर चुनौतीपूर्ण रहा। उनके बयानों ने बार-बार यह जताया कि अमेरिका को केवल लाभ की भाषा समझ आती है। लेकिन भारत ने जो धैर्य, विवेक और रणनीति दिखाई, वह अब एक स्थायी विदेश नीति की नींव रखती है। अमेरिका में बदलते नेतृत्व और वैश्विक राजनीतिक उठापटक के बीच, भारत को अपनी दिशा स्वयं निर्धारित करनी होगी।

भारत को अब यह तय करना होगा कि वह राष्ट्रवाद के नारों से आगे बढ़कर आर्थिक आत्मनिर्भरता को वास्तविक रूप दे। 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'स्टार्टअप इंडिया' जैसे अभियानों को ज़मीनी स्तर पर सफल बनाना ही अमेरिका जैसे देशों की नीति पर प्रभाव डाल सकता है। कूटनीति के इस युद्ध में भारत को तलवार नहीं, तराजू उठाना है, ऐसा तराजू जिसमें उसके हितों का संतुलन स्थिर और अडिग रहे। और जब तक भारत अपने हितों की रक्षा इस विवेक के साथ करता रहेगा, तब तक कोई ट्रंप, कोई डॉलर, उसकी संप्रभुता को झुका नहीं सकेगा।

सुशासन की प्रतीक अहिल्या बाई का स्मरण

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया
लेखक स्तंभकार हैं।

इस सप्ताह मध्यप्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर खबरों में रही। इंदौर के सुर्खियों में रहने का कारण था मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुआई में कैबिनेट बैठक का राजवाड़ा में आयोजन। मोहन यादव सरकार की यह कैबिनेट बैठक वास्तव में लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर के सुशासन और न्याय को याद करने के लिए आयोजित की गई थी। इस आयोजन का अवसर है अहिल्या बाई की 300 वीं जयंती। मध्य प्रदेश सरकार ने देवी अहिल्या बाई होल्कर की 300 वीं जयंती के आयोजन के लिए समिति का गठन किया है।

इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर के अवदान पर अध्ययन और शोध को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। सरकार देवी अहिल्या बाई द्वारा निर्मित मंदिरों, पूजा घरों, धर्मशालाओं और अन्य सामुदायिक उपयोग की संरचनाओं के रख-रखाव के कार्य करेगी। लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर के महाराष्ट्र स्थित मूल गांव चौड़ी में विशेष दल भेजकर आवश्यक जानकारियों का एकत्र करवाया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न भागों में अहिल्या यात्रा के आयोजन, शाला व महाविद्यालय स्तर पर देवी अहिल्या पर केन्द्रित शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए।

लोकमाता देवी अहिल्या बाई के त्रिशताब्दी समारोह का मुख्य कार्यक्रम 31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान में होगा। महिला सशक्तिकरण पर केन्द्रित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में भारत सरकार की ओर से लोकमाता देवी अहिल्या को समर्पित डाक टिकट और सिक्के का लोकार्पण भी प्रस्तावित है।

मध्य प्रदेश सरकार जिन गौरवयी अहिल्या बाई की स्मृति में विभिन्न आयोजन कर रही हैं, उनके बारे में जानना महत्वपूर्ण होगा। हमारे इतिहास में बहुत सी शूरवीर स्त्रियों के नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित है। इन सब नामों में 18 वीं शताब्दी में मालवा की महारानी के रूप में प्रसिद्ध अहिल्याबाई होलकर का नाम भी आता है। वे व्यापक रूप से अपने साहस और प्रशासनिक कुशलता के कर्ण जानी जाती है। अपने 18 वर्षों के शासनकाल में रानी से माता अहिल्याबाई का सफर तय करना इतना आसान नहीं था लेकिन अपनी सूझ-बूझ और लगन और समाज के उत्थान के लिए कई कार्य किए और लोगों के कल्याण के लिए हमेशा समर्पित रही।

सनातन के लिए उनका समर्पण आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ जैसे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाने के साथ-साथ कृषि के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया। वह नारीवादी शासक होने के साथ-साथ बहादुर योदा भी थी। पितृसता के उस दौर में समाज की बेड़ियों को तोड़कर इतिहास में अपनी जगह बनाई। उनकी दूरदर्शिता का अंदाजा यही से लगाया जा सकता है कि उस समय में उन्होंने प्राप्त होने वाले टैक्स को सामाजिक सशक्तिकरण का जरिया बनाया। उनके द्वारा किए गए हर कार्य से उन्होंने अपनी आगामी हर पीढ़ी को यह संदेश दिया है कि यदि हमें स्वयं पर भरोसा हो तो अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को भी हम अवसर में परिवर्तित करके न सिर्फ अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते है बल्कि आने वाले हर इंसान के जीवन की उम्मीद की किरन बनकर युगों युगों तक दी जाने वाली मिसाल बन सकते हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

सुरेश उपाध्याय
लेखक व्यंग्यकार हैं।

'आग लगने पर कुआं खोदना' आज तंज नहीं वक्त की हकीकत

जब जैसी जरुरत होती है, उस अनुरुप व्यवस्था जुटाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब आग को ही ले लीजिए, जब लगेगी तब ही बुझाने के लिए पानी की जरुरत महसूस होगी। पानी की जरुरत पर कुंआ ही याद आएगा। आग कब व कहां लगेगी इसका पूर्वानुमान तो नहीं किया जा सकता है तो एडवांस में कुंआ कहीं भी खोद लें? जब, जहां जरुरत होगी खोद लेंगे। कभी भी, कहीं भी खोद लेने में समय व संसाधन क्यों नष्ट करें?

हमारे पूर्वजों ने जो कुंए, बावडी, तालाब आदि बनाए थे उन्हें भी हमने इसलिए अपने हाल पर छोड दिया था। अनावश्यक संसाधन उनकी देखरेख/ रखरखाव में खर्च नहीं किए थे। जब आग लगेगी (उपयोगिता होने पर) साफ, सफाई, पुनर्जीवन कर लेंगे। इसी तरह सीवरेज, औधोगिक अपशिष्ट आदि को नदियों/ तालाबों में छोड़ दिया था।

सहज, सुलभ, सस्ती इस व्यवस्था पर अलग से कोई खर्च न कर कितनी राशि व संसाधन इतने वर्षो में बचाए गए हैं?, इसका आकलन आसान नही है। अतिक्रमण ने भी नदियों के प्रवाह व जल स्त्रोतों की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। व्यवस्था ने लोगों पर भरोसा किया और कुछ ने तालाब, कुंओं, नदी व कैचमेंट एरिया पर अतिक्रमण कर लिए, कॉलोनी बसा दी। भोले-भाले लोगो ने रिस्क (जोखिम) लेकर, उधार लेकर, अपनी जीवनभर की कमाई को दांव पर लगा दिया और इन हिस्सों में आशियाने बना लिए।

अब जब जलसंकट सामने हैं तो साफ-सफाई की पहल की जा रही है। एसटीपी (स्पेशिअल ट्रीटमेंट प्लांट) लगाए जा रहे हैं। अतिक्रमण व आशियाने का क्या करे, अब उन पर बुलडोजर चला दें? बुलडोजर के पास और कोई काम नहीं है? काम के बोझ व अन्य प्रकार के दबाव से जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी यदि कोई कार्रवाई समय पर नहीं कर पाए या अनदेखी की, तो उन्हें जिम्मेदार ठहरा दें? अधिकारियों-कर्मचारियों को निरुत्साहित करने का संदेश दें?

अपने कार्यबल का मनोबल बनाए रखना नियोक्ता को तय करना होता है। कहने का आशय यह कि जरुरत पडने पर जो किया जाना चाहिए, किया जा सकता है, वह सब किया जा रहा है।

समय, संसाधन व ऊर्जा को बचाने के लिए ही वर्षाकाल में हमें नदी, कुंए, बावडी आदि की सफाई, पुनर्जीवित करने की याद आती है और हम सारे संसाधन झोंक देते हैं। यह अलग बात है कि बरसात का पानी किनारे की गाद को फिर नदी, तालाब, कुंए में प्रवाहित कर हमारी मेहनत पर पानी फेर देता है। गंगा, यमुना समेत देशभर की छोटी बडी नदियों की सफाई को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, विशेष (स्पेशल) ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। इतने बरस इनको खराब करने में लगे है तो सुधार के लिए धैर्य रखना होगा, निरंतर प्रयास करना होंगे और इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। जो भरोसा दिला रहे हैं, उनके भरोसे पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा? आलोचना करना आसान काम है। विपक्षी का काम विरोध करना है, जो विपक्ष में होता है वह विरोध नही करेगा तो क्या करेगा? स्थिति बदलने पर परस्पर भूमिका बदलना भी स्वाभाविक है।

इसी प्रकार तेज गर्मी में ही हमें ग्लोबल वार्मिंग की समस्या तथा वृक्षों का महत्व याद आता है। विकास के लिए पेड़ काटने ही पडते हैं। पेड़ों की महत्ता समझते हुए ही किसी योजना की अनुमति के साथ पेड़ काटने से कई गुना पौधे रोपने की शर्त सम्बंधित एजेंसी जोड़ देती है तथा अपने दायित्व की इतिश्री कर देती है। इसी प्रक्रिया में जितने वृक्ष काटते है, क्रियान्वयनकर्ता उससे कई गुना अधिक पौधारोपण कर शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करते है। अब यह पौधे पनपे नहीं, सूख जाए, मर जाए तो कोई क्या कर सकता है? इससे इत्तर पर्यावरण सरंक्षण अभियान में पौधारोपण के रिकार्ड बनाने के कई प्रयास भी किए जाते हैं, उनके प्रत्येक के उल्लेख करना हमारा अभिष्ट नहीं है। अब इन विशेष अभियानों के भी बडी संख्या में पौधे पेड न बन पाए तो अभियानकर्ता क्या कर सकते हैं? उनके पास आत्मसंतुष्टी व दूसरों को दिखाने के लिए नामचीन संस्थाओं के प्रमाणपत्र हैं। यह प्रमाणित करते है कि हमारी ओर से प्रयास में कोई कमी नहीं रही है।

हमारे देश के महानगर बेंगलुरु का ही हाल ही का भीषण जलसंकट हमने देखा है और मानसून पूर्व की बारिश में बाढ़ व डूब के दृश्य भी देख रहे हैं। समय समय पर पानी की व्यवस्था व डूब से बचाव के कार्य किए जा रहे हैं कि नहीं? कुछ वर्ष पूर्व ऐसे ही दृश्य चेन्नई में भी देखे गए थे और वक्त पर जरुरी व्यवस्थाएं की गई थी। 'आग लगने पर कुआ खोदना' आज तंज करने का मुहावरा नही वक्त की हकीकत है।

पर्यटन में भी सूखा झेल रहा है बुंदेलखंड

पर्यटन

डॉ. मनीष जैसल

लेखक पत्रकारिता के अध्यापक हैं।

कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा के साथ हमने इस यात्रा की शुरुआत की। प्रमुख द्वार से लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा हमें अचंभित करती है। लेकिन इस परिक्रमा में इस कस्बे की दयनीय स्थिति दिखती है। कहीं से ऐसा नहीं लगता कि यह वही जगह है जहां इस देश के सबसे बड़े भगवान में से एक श्री राम ने वनवास यहीं काटा। परिक्रमा के दौरान हम यही बात करते रहे कि यह जगह अभी भी वनवास से कम नहीं है। कामता नाथ की इस परिक्रमा में मनोकामना पूर्ण होती है ऐसी मान्यता भी है।

पिछले दिनों बुंदेलखंड भ्रमण के लिए निकला। चित्रकूट, मैहर, पन्ना और खजुराहो जैसे धार्मिक और रमणीय स्थल वाले शहर शामिल थे। चित्रकूट के पास मऊ कस्बे में मेरा बचपन बीता है, इसलिए इस जगह से मेरा आत्मीय जुड़ाव है। लेकिन 20 साल बाद भी चित्रकूट की हालत वैसी की वैसी देखकर यह लिखने को मजबूर होना पड़ रहा है।

कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा के साथ हमने इस यात्रा की शुरुआत की। प्रमुख द्वार से लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा हमें अचंभित करती है। लेकिन इस परिक्रमा में इस कस्बे की दयनीय स्थिति दिखती है। कहीं से ऐसा नहीं लगता कि यह वही जगह है जहां इस देश के सबसे बड़े भगवान में से एक श्री राम ने वनवास यहीं काटा। परिक्रमा के दौरान हम यही बात करते रहे कि यह जगह अभी भी वनवास से कम नहीं है। कामता नाथ की इस परिक्रमा में मनोकामना पूर्ण होती है ऐसी मान्यता भी है।

कामदगिरी की परिक्रमा के बीच में ही आपको रोप वे या पैदल यात्रा के जरिए लक्ष्मण पहाड़ी जाने का भी अवसर मिलेगा। इतने ऊपर चढ़कर भी हमने यही देखा कि स्थिति यहाँ की बदले तो यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यहाँ एक वैद्य जी जरूर मिले जो करीब 40-50 लोगों का जड़ी बूटी से इलाज कर रहे थे। संभवतः उनके पास हर मर्ज की दवा भी थी।

40 डिग्री तापमान में घूमने के बाद हमने अपनी मनोकामना लिए यह परिक्रमा पूरी की। और आगे बढ़ते हुए गुप्त गोदावरी पहुँचें। चूंकि मैं यहाँ वर्षों से आता रहा हूँ इसलिए रोमांचित तो नहीं था लेकिन मुझे यह जरूर लगा था कि अब कुछ बदल सा गया होगा। लेकिन इस बार यहाँ भी स्थिति वैसी की वैसी थी। मेरे साथी लोग इस जगह को देखते हुए जरूर रोमांचित थे लेकिन सवाल अब भी यहीं कि इतनी खूबसूरत जगह फिर भी ऐसी नीरस सी क्यों बनी है। पर्यटकों के लिए यह जगह बहुत अच्छी हो सकती है। गोदावरी से निकलते ही भूख लगने लगी। आस पास कोई भी ढंग का होटल नहीं। ये मानिए आपके शहर का सबसे बदतर होटल यहाँ के लिए बेस्ट था। 70 रुपये में भरपेट खिलाने वाला ढाबा टाइप। जहां न हाइजीन का ख्याल न बैठने की व्यवस्था। बस आपका पेट भर जाएगा जैसी तैसे।

हमने खाने की बजाय हल्का फुल्का स्नैक्स/ड्रिंक्स लेकर आगे सती अनुसूईया चल दिए। वहाँ जाकर मंदाकिनी नदी के किनारे बैठ सुकून सा मिलने लगा। लेकिन गहराई से देखा तो यकीन मानिए आपके गाँव की नदी यहाँ से ज्यादा साफ मिलेगी। वन विभाग ने जो आस पास के घरों की तबाही मचाई है उसके भी क्या कहने। दर्शनार्थी बनकर गए थे लेकिन बार बार यही आया लोग यहाँ क्यों आएंगे ? मछलियों और बंदरों को खिलाने के बाद हम लोगों ने स्फटिक शीला और हनुमान धारा की ओर कदम बढ़ाए। वहाँ भी स्थिति जस की तस। थक हार के रामघाट में अपने होटल पहुंचे। चेंज करने के बाद रामघाट की आरती के लिए पहुंचे। मंदाकिनी के एक ओर यूपी और दूसरी ओर एमपी लगता है। दो आरती होती है। यहाँ एक बात समझ आती है स्थिति बाद से बदतर तो यहाँ भी थी हैं लेकिन यूपी वाले घाट और भी बुरी स्थिति में हैं।

अब बारी डिनर करने की थी। शहर में एक दो होटल ही लोगों की जुबान पर चढ़े हैं। जिसमें एक है अन्नपूर्णा होटल, यह वहीं होटल हैं जहां शहर के कलेक्टर और जीएसटी ऑफिसर तक भोजन करते हैं। दोनों हमारे बगल वाली टेबल पर थे। चूंकि रिपोर्टिंग के मूड में थे नहीं इसलिए बिना बात किए खाने पर फोकस किया और

भोजन कराने वाले भाइयों पर फोकस किया। सुकून भरा भोजन करने के बाद आकर सो गए और सुबह निकल पड़े मैहर की ओर। रोप वे का टिकट कटाया और शरद माता के दर्शन किए। रोपवे से वापसी में होने वाली अव्यवस्था और घपलेबाजी को फ़ील करते हुए मन को शांत रखा और निकल पड़े पन्ना और खजूराहों की ओर।

यह हमारी यात्रा में पहले शामिल पड़ाव नहीं था। चूंकि चित्रकूट मैहर से यात्रा का दिल नहीं भरा तो मंदिरों के शहर की ओर निकलना पड़ा। रास्ते में पन्ना नेशनल पार्क था लेकिन धूप ने इजाजत नहीं दी। आगे बढ़े तो पांडव फाल्स का बोर्ड दिखा। इस बार धूप हमें रोक नहीं पाई।

वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों मान्यताओं से भरी पूरी इस लोकेशन को अगर आप देखेंगे तो मन को वाकई शांति मिलेगी। लेकिन टूरिज़्म बोर्ड नया जाने क्यों इसे वैसा नहीं सहेज पा रहा जैसा उसे करना चाहिए था। देश के बाहर की लोकेशन से बेहतर है ये जगह। सुकून इतना कि दिल हँस पड़ेगा।

धूप बढ़ती जा रही थी। हम खजूराहों पहुँच चुके थे। मंदिरों के शहर में थे, इसलिए शहर में घुसते ही नगर पालिका वालों ने हमारी कार की पर्ची काट दी, उधर गाइड ने हमें घेर लिया। 16 मंदिरों में से बेस्ट 4 मंदिर दिखाने का वादा करके वो हमारे साथ हो लिए।

700-800 साल पुरानी कहानियाँ सुनाते हुए गाइड ने हमें मंदिरों में बने चित्रों की गहराई बनाने लगा। हमारे साथ एक महिला मित्र साथ थी, उन्हें बड़ा अजीब लगा की गाइड बार-बार मेरे कान में ऐसा क्या खास बात रहा है जो वो नहीं सुन सकती। खैर, उन्होंने कामसूत्र पर एक लंबा लेक्चर गाइड को देते हुए कहा कि आपके हम तीन टूरिस्ट को घूमने लाए हैं इसलिए खुल कर बोलिए।

शाम हो चली थी। खजुराहो के मंदिरों ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया था। कहते हैं यह मंदिर धूप के अनुसार अपना रंग बदल देते हैं या फिर हमारी आंखें वैसा देखने लगती हैं।

सुकून भरी इस यात्रा में यह पहली जगह थी जहां लगा कि सरकार ने इस जगह को विश्व धरोहर की वहाग से ही सही सहेजने की कोशिश की हैं। लेकिन ऑफ सीजन में भी सरकार को वैसा ही संरक्षित करना चाहिए। कोई ऐसा संग्रहालय भी हो जहां से खजुराहो की पूरी अधिकृत जानकारी मिल सके। नहीं तो आप भी मर्दवादी सोच के साथ यही समझ पाओगे कि वर्षों पहले महिलाएं ही मर्दों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। (ऐसा गाइड की बातों से लगा)।

इस यात्रा के बाद रास्ते में बागेश्वर धाम भी पड़ा लेकिन वहाँ का टूरिज़्म प्रमोशन हम टीवी पर खूब देख चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हुए वाया झांसी हम खूबसूरत पलों के साथ ग्वालियर या गए। अब उम्मीद करते हैं दोबारा इन शहरों में जाए तो इनकी स्थिति में जरूरी बदलाव जरूर जाएं। हमारा पूरा ध्यान अयोध्या, काशी, उज्जैन पर रहेगा तो हम अपनी रामायण के सबसे बड़े किरदार चित्रकूट को धीरे-धीरे खत्म होते भी देख लेंगे। सरकार को तुरंत इस ओर ध्यान देने की जरूरत हैं। धार्मिक पर्यटन देश का उभरता हुआ क्षेत्र हैं लेकिन सरकार सिर्फ उन्हीं स्थानों पर जोर दे रही हैं जहां धार्मिक विवाद है। ऐसे में उनकी मंशा संदेह के घेरे में रहती है। हमें चित्रकूट, मैहर, खजुराहो जैसे धार्मिक स्थलों पर ध्यान देकर यहाँ के लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं पन्ना के पांडव फाल्स जैसी लोकेशन फिल्म शूटिंग के लिहाज से बेहतर हैं उसे ऐसे आयोजनों के लिए भी ओपन करना चाहिए। गर्मियों में इन जगहों पर लोग कम जाते हैं लेकिन जितनी तल्लीनता से आप इस मौसम में यहाँ घूम सकेंगे वो आपको हमेशा याद रहेगा। फिलहाल ऐसा लगा जैसे पर्यटन में भी सूखे की मार झेल रहा है बुंदेलखंड।

जब सबसे ज्यादा जरूरत है तब ही चले गए जयंत नार्लीकर

स्मृति शेष

मनोज निगम

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

पिछले साल पहले पुणे स्थित 'आयुका' (इंटर-युनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रॉनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी का अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र) के परिसर में जाने का मौका मिला था। जब तक कोई ना बताता, तब तक मालूम ही नहीं होता कि परिसर के अन्दर विज्ञान वाटिका में अन्य पेड़ों की तरह वो खास पेड़ भी था जिसको न्यूटन के सेब के पेड़ का वंशज कहा जाता है। यह पेड़ इंग्लैंड के उस सेब के पेड़ की कलम से लगाया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है उसके नीचे न्यूटन को गुरूत्वाकर्षण का विचार आया था। विज्ञान के इतिहास को याद करने के लिए यह पहल जयंत नार्लीकर ने की थी।

मूलतः 'मराठी विज्ञान परिषद्' में और बाद में बाल-विज्ञान पत्रिका 'चकमक' में प्रकाशित अपने एक लेख में जयंत जी ने बताया था कि दिसम्बर 1988 में 'आयुका' की स्थापना के बाद हमेशा उनकी कोशिश इस संस्थान के बारे में जानकारी देने की रहती है। 1999 में आस्ट्रेलिया के सिडनी में एक स्लाईड शो दिखाया जा रहा था, जिसमें 'आयुका' के परिसर के प्रमुख आंगन में आर्यभट्, गैलीलियो, न्यूटन एवं आईन्स्टाईन की मूर्तियां नजर आ रही थीं। इनमें न्यूटन की मूर्ति निगाहें नीची किए सेब को देख रही हैं। यह मूर्ति बरगद के एक बड़े पेड़ के नीचे है।

इसे देखकर नार्लीकर जी ने मजाक में कहा कि शायद न्यूटन सोच रहा है कि बरगद के पेड़ से सेब कैसे गिरा? जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, वैज्ञानिक रान ईकर्स ने सुझाव दिया कि क्यों ना न्यूटन की मूर्ति के पीछे उसी सेब के पेड़ का वशंज लगाया जाए? उनका सुझाव सभी को बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चुनौतियों को पार करने के बाद परिसर में न्यूटन के सेब के पेड़ का वशंज लगाया गया।

विज्ञान का खुद का इतिहास है, वैज्ञानिकों को नई-नई कल्पनाएं सूझती हैं, साथ ही उनसे गल्तियां भी होती हैं। खुद न्यूटन इन दोनों में माहिर थे। इसी तरह वैज्ञानिक जिन यंत्रों के माध्यम से खोज करते हैं, उनका भी इतिहास में अपना महत्व होता है। इसलिए उन्हें प्रयोगशाला में रखा जाता है, इससे प्रेरणा भी

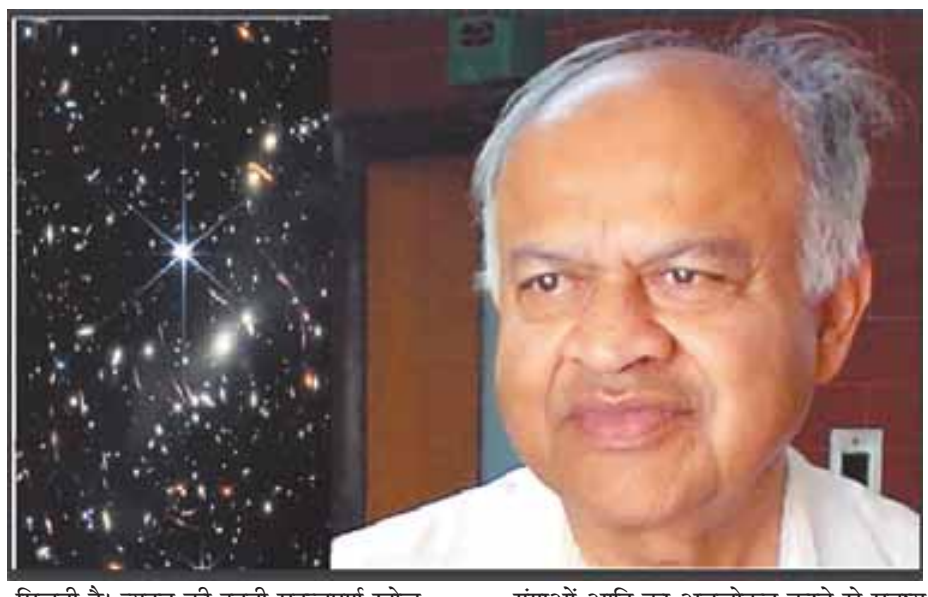

मिलती है। न्यूटन की इतनी महत्वपूर्ण खोज का सम्बन्ध इस पेड़ से जुड़ा है, इसलिए उसके वशंज को बच्चों के सामने खड़ा करना मुमकिन हुआ।

बहुत लोग यह कहते हैं कि एप्लाइड साईंस में खगोल विज्ञान का महत्व नहीं है। कुछ पूछते हैं कि दूर-दूर तक फैले ग्रहों-तारों, आकाश-गंगाओं आदि का अवलोकन करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? इस तरह के जवाबों के लिए भी नार्लीकर जी ने विज्ञान प्रसारक की भूमिका निभाई। आपने मराठी, अंग्रेजी और हिन्दी में भी लेखन कार्य किया, बहुत सारी विज्ञान-कथाएं और पुस्तकें लिखीं। उनकी आत्मकथा 'चार नगरातले माझे विश्व' के लिए उन्हें 'साहित्य अकादमी' पुरस्कार भी दिया गया। बच्चों में विज्ञान के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने के लिए दूरदर्शन पर 'ब्रम्हांड' नामक धारावाहिक शो की परिकल्पना और पटकथा भी नार्लीकर जी ने लिखी थी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई। इस कार्यक्रम में वे बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करने का भी प्रयास करते थे।

जयंत नार्लीकर ने ब्रम्हांड की उत्पत्ति और विकास सम्बंधी परिकल्पनाओं पर शोधकार्य किया था। 'आयुका' संस्थान को बनाने में उनकी विशेष भूमिका रही थी, वे 'आयुका' के संस्थापक-निदेशक भी रहे थे। खगोल शास्त्र और खगोल भौतिकी में उनके योगदान के लिए 'शांति स्वरूप भटनागर' पुरस्कार, 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार जैसे अनेकों पुरस्कारों के साथ 1965 में पद्मभूषण और 2004 में पद्मविभूषण दिया गया। आज के दौर में जब टेक्नॉलाजी के अच्छे और बुरे प्रभावों से समाज जूझ रहा है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और वैज्ञानिक मानसिकता तैयार करने की समाज में बहुत जरूरत है। ऐसे में जयंत नार्लीकर जैसी शख्सियत का जाना आज की बहुत दुखद घटना है। (सप्रेस)

राजनेता बोलें तो तोल-मोल कर बोलें

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।

सत्ता हासिल करने के पश्चात जातीय एवं क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए अधिकांश पदों का पदभार सौंपे जाने का चलन है। हालांकि अनुभव को भी तवज्जो दी जाती है, लेकिन जो तथाकथित अनुभवी होते है, उनमें से भी अधिकांश अपने सोच विचार के दायरे से बाहर नहीं आ पाते। दरअसल इनके अपने पूर्वाग्रह हुआ करते हैं। जिसके चलते इनके गैरजिम्मेदाराना वक्तव्य अनेक अवसरों पर सत्ता एवं संगठन के लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाते हैं। कई अवसर ऐसे भी आते हैं जब संबंधित के राजनीतिक वर्चस्व को देखते हुए दलीय के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में सत्ता एवं संगठन को राजनीतिक लाभ अथवा हानि पर विचार करना होता है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में मामले को ठंडा बस्तों में डाल दिया जाता है।

सचमुच बहुत आश्चर्य होता है जब प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय नेता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में ऐसी-ऐसी अजीबोगरीब टिप्पणी जड़ देते है कि देखते ही देखते रायता फैल जाता है। अब सक्रिय राजनीति के लिए या यूं कहा जाएं कि सत्ता में भागीदारी के लिए किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता या व्यावहारिकता का कोई आवश्यक पैमाना नहीं है। इसके चलते बौद्धिक दृष्टि से अपरिपक्व किंतु धनबल, बाहुबल और जाति बल के चलते अनेक शख्सियत भी राजनीतिक जगत में अपनी गहरी पैठ बना लेती है। साथ ही सत्ता एवं संगठन में महत्वपूर्ण पद भी प्राप्त कर लेती है। एक प्रकार से इन्हें झेलना संबंधित राजनीतिक दल की राजनीतिक विवशता हो जाती है। जो कि कई बार सत्ता एवं संगठन को भारी पड़ जाती है।

सत्ता हासिल करने के पश्चात जातीय एवं क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए अधिकांश पदों का पदभार सौंपे जाने का चलन है। हालांकि अनुभव को भी तवज्जो दी जाती है, लेकिन जो तथाकथित अनुभवी होते है, उनमें से भी अधिकांश अपने सोच विचार के दायरे से बाहर नहीं आ पाते। दरअसल इनके अपने पूर्वाग्रह हुआ करते हैं। जिसके चलते इनके गैरजिम्मेदाराना वक्तव्य अनेक अवसरों पर सत्ता एवं संगठन के लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाते हैं। कई अवसर ऐसे भी आते हैं जब संबंधित के राजनीतिक वर्चस्व को देखते हुए दलीय के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में सत्ता एवं संगठन को राजनीतिक लाभ अथवा हानि पर विचार करना होता है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में मामले को ठंडा बस्तों में डाल दिया जाता है।

वैसे इतना जरूर है कि गांव के चाय पान के ठिए से लेकर शहरी कॉफी हाउस में बैठकर हर कोई आम नागरिक स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विषयों पर साधिकार चर्चा करें, तो इसमें किसी को कतई कोई खास आपत्ति नहीं होती। दरअसल आम नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर।जितना स्वतंत्र है, उतनी स्वतंत्रता का परिचय किसी भी छोटे बड़े पद पर विराजमान शख्सियत द्वारा नहीं दिया जा सकता। किस पद पर रहकर किन्होंने कौन सी बात कही है ? तद्नुसार ही उस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं का दौर चला करता है। यह नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी। जिसके चलते कई अवसरों पर अनावश्यक तनाव की स्थिति भी निर्मित हो जाया करती है।

इसके अतिरिक्त हर एक पद की अपनी एक अलग ही मर्यादा हुआ करती है। वैसे भी किसी पद पर आरूढ़ शख्सियत को अपने पद के अनुरूप ही किसी मामले में प्रतिक्रिया देना चाहिए। जो विषय उनके कार्यक्षेत्र या अधिकार क्षेत्र के सर्वथा बाहर हो, जिस विषय का स्तर राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय हो और यदि कोई मामला अत्यंत संवेदनशील हो, ऐसे में उथली सोच का प्रदर्शन ठीक नहीं। अनेक अवसरों पर ऐसा होने पर बड़ी विचित्र स्थिति निर्मित हो जाती है। वैसे भी हर किसी घटनाक्रम को

लेकर नितांत व्यक्तिगत अभिमत पद के आभामंडल से आलोकित होता है। कहीं गई बात का कुछ वजन यह भी होता है कि किस पद पर रहते किसने क्या बात कही है ? ऐसे में व्यर्थ के बवाल को टाला नहीं जा सकता। हर एक पद का कार्यक्षेत्र भी अलग-अलग स्तर का होता है। यह स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का हो सकता है। वैसे ऐसा कार्यक्षेत्र विभाग विशेष तक भी सीमित हो सकता है। इसलिए जब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई अत्यंत संवेदनशील घटनाक्रम हो, राष्ट्र के या सेना के मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रश्न हो और उस पर राजनीतिक नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया गया हो, उस पर किसी प्रकार की आक्रामक टिप्पणी करने से बचना जरूरी है। अन्यथा अनावश्यक रूप से बात का बतंगड़ बनने में देर नहीं लगती। यही नहीं कभी-कभी तो इसके चलते हमारे अपने उच्च स्तरीय राजनीतिक नेतृत्व को भी शर्मिंदा होने की स्थिति निर्मित हो सकती है।

दरअसल जो जहां जिस पद पर होते हैं, उन्हें उस पद की सीमा का ज्ञान जरूरी है। वैसे भी आजकल तकनीकी संचार सुविधाएं इतना विस्तार पा चुकी है कि पलक झपकते ही कोई बात जाने कहां से कहां पहुंच जाया करती है। ऐसे में जो जिस स्तर पर पद पर होते हैं, उनके कद एवं पद के अनुरूप उनके कथन या व्यवहार को मीडिया द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जाता है। ऐसी स्थिति में आपत्तिजनक बोल अनेक अवसरों पर उनके राजनीतिक नेतृत्व के लिए भारी पड़ जाते हैं। इसलिए किसी भी छोटे-बड़े जिम्मेदार पद पर विराजित शख्सियत को हर किसी बात पर प्रतिक्रिया देना उन्हें गहरे संकट में ला सकता है। इस बात पर गौर करना जरूरी है।

आते ही खराब हो गया था 10 लाख का ताप्ती सरोवर का फव्वारा

नगर पालिका अधिकारी ने फव्वारा सप्लायर कंपनी को भेजा नोटिस

बैतूल/मुलताई। मुलताई के ताप्ती सरोवर सौंदर्यीकरण के लिए ताप्ती सरोवर के मध्य लगाया गया फव्वारा आते ही खराब हो गया था, जिसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे थे। इस फव्वारे को निकालकर नगर पालिका परिसर में रख लिया गया था। जिसको लेकर हाल ही में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीरेंद्र तिवारी ने फव्वारा सप्लाई करने वाली कंपनी एआरएएम टेक्नोट्रैक भोपाल को नोटिस जारी कर तीन दिवस के अंदर उच्च गुणवत्ता युक्त फव्वारा ताप्ती सरोवर में लगाने को कहा है। सप्लायर को दिए गए

इस नोटिस में कहा गया है कि नगर पालिका से फव्वारे को लेकर किए गए अनुबंध के अनुरूप उच्च गुणवत्ता और मापदंडों के आधार पर फव्वारा ताप्ती सरोवर के मध्य समय सीमा में लगाए अन्यथा ठेका निरस्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि जो फव्वारा नगर पालिका को भेजा गया है वह अनुबंध के अनुरूप नहीं है जिसके कारण नगर पालिका की छवि खराब हो रही है। यहां उल्लेखनीय है कि बीते दिनों 10 लाख रू. 12000 की लागत से ताप्ती सरोवर के मध्य आधुनिक लाइटिंग युक्त फव्वारा लगाया जाना था टेक्नो ट्रैक कंपनी से मुलताई नगर पालिका ने अनुबंध किया जिसके आधार पर फव्वारा मुलताई पहुंचा किंतु फवारा लगते ही खराब हो गया जिसको लेकर नगर में तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त हो गई हालांकि नगर पालिका ने इस फवारे का भुगतान नहीं किया था। फरवरी में खराबी आने के बाद इसे लाकर नगर पालिका परीसर में रख दिया गया था जो आज भी वही रखा है। हाल ही में आए नगरपालिका अधिकारी वीरेंद्र तिवारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सप्लायर कंपनी को नोटिस जारी कर तीन दिवस में अनुबंध के अनुरूप फवारा ताप्ती सरोवर के मध्य लगाने का कहा है।

10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का किया समापन

बैतूल। सक्षम जीवन कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन उत्साहपूर्वक किया गया। इस शिविर का आयोजन कम्युनिटी यूथ लीडर अविनाश राठौर द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय चिचोली में किया गया, जिसमें बच्चों को समय प्रबंधन, रचनात्मक गतिविधियां और टीमवर्क जैसी महत्वपूर्ण जीवन दक्षताओं का प्रशिक्षण दिया गया। इस शिविर में 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास, संवाद कौशल तथा नेतृत्व क्षमता का विकास करना रहा। कैम्प के दौरान बच्चों ने चित्रकला, समूह चर्चा, कहानी लेखन और अन्य गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की। साथ ही उन्हें निर्णय लेने, समस्या समाधान, तथा भावनात्मक समझ जैसे जीवन कौशल विषयों पर भी मार्गदर्शन प्रदान किया गया।बाल मेला के रूप में आयोजित समापन कार्यक्रम में बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने के लिए स्थानीय अभिभावक भी उपस्थित रहे और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस आयोजन के माध्यम से सीवायएल ने सामुदायिक नेतृत्व में अपनी भूमिका को और भी मजबूत किया है। समर कैंप न केवल जीवन कौशल विकास का प्रभावशाली उदाहरण बना, बल्कि युवा नेतृत्व की एक प्रेरणादायी मिसाल भी प्रस्तुत की। कार्यक्रम के समापन अवसर पर सीएसी बाली सरोने विशेष रूप से उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधान पाठक मधुसूदन राठौर तथा शिक्षक साथियों का भी विशेष सहयोग रहा। ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक इंद्रसेन नागले ने अपने उद्बोधन में बच्चों और शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

एक दिवसीय कृषक सम्मेलन सह-कार्यशाला 24 मई को

मूंग की खेती के विकल्पों पर कृषि वैज्ञानिक करेंगे प्रबोधन

बैतूल। मप्र जन अभियान परिषद और भारत भारती शिक्षा समिति के संयुक्त तत्वावधान में मूंग की वैकल्पिक फसलों को उपजाने के लिए कृषकों को प्रेरित-प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक दिवसीय कृषक सम्मेलन सह-कार्यशाला का आयोजन 24 मई 2025 को भारत-भारती परिसर में किया जाएगा।सम्मेलन में चयनित कृषकों को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संबोधित करेंगे। मप्र जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन की प्राथमिकता मूंग की फसल उत्पादन से प्रकृति और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए मूंग की वैकल्पिक फसलों को प्राथमिकता और प्रोत्साहन देने की है। इस दृष्टि से किसानों और संबंधित समाज का उन्मुखीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मप्र जन अभियान परिषद् ने इस दिशा में पहल करते हुए भारत भारती शिक्षा संस्थान के साथ यह आयोजन किया है। आयोजन में मूंग उत्पादक कृषकों के साथ जैविक कृषि करने वाले कृषक भी सम्मिलित होंगे। इस दिशा में होने वाले नवाचार के आयामों पर भी विचार विमर्श होगा। उपाध्यक्ष श्री नागर ने बताया कि मिट्टी सुपोषण, मानव स्वास्थ्य और स्वस्थ पर्यावरण की दिशा में यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कृषक समुदाय की सहभागिता महत्वपूर्ण होगी।

मुख्यमंत्री के सभा स्थल का विधायक, कलेक्टर एवं एसपी ने किया निरीक्षण

बैतूल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आगामी 28 मई को सारणी दौरा प्रस्तावित है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर गुरुवार को आमला सारणी विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, एसपी निश्चल झारिया, नगर पालिका अध्यक्ष किशोर बरदे, उपाध्यक्ष जगदीश पवार, पार्षदगण व अन्य अधिकारियों ने सभा स्थल, हवाई पट्टी, हेलीपैड स्थल और पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 28 मई को सारणी के बगडोना हवाई पट्टी पर सभा को संबोधित करेंगे। बुधवार को विधायक व कलेक्टर, एसपी ने सभा स्थल पर निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने डोम टेंट लगाने, सुरक्षा व्यवस्था, बैरेकेटिंग करने सहित अन्य व्यवस्था करने के निर्देश दिए। हेलीपैड का कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। उन्होंने पार्किंग स्थलों का भी निरीक्षण किया। संभावित जनदर्शन रूट का भी अधिकारियों ने सर्वे किया।

परिवार को बंधक बनाकर नकाबपोशों ने की लाखों की डकैती

एएसपी मौके पर पहुंची, घटनास्थल से मिले पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग

● **छत से घर में घुसकर 5 लाख नगद और लाखों के जेवरात की लूट**

बैतूल/आमला। आमला में रतेड़ा रोड स्थित चंद्रभागा नदी के पास अनाज एवं गुड़ व्यापारी के घर बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात लगभग 3 बजे लाखों की डकैती होने से नगर में दहशत का माहौल है। लुटेरों ने फरियादी कल्लू उर्फ कल्लूलाल प्रजापति निवासी आमला के घर से करीब 5 लाख रुपए नगद और लगभग 9 लाख के अलमारी मे रखे सोने-चांदी के जेवरात लूट ले गये। आरोपियों ने घर में मौजूद 7 साल के मासूम बच्चे पर चाकू अड़ाकर परिवार को डराया और जमकर मारपीट की। व्यापारी के सिर पर डंडे से हमला कर घायल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गल्ला व्यापारी कल्लू प्रजापति और उनकी पत्नी तथा 7 वर्षीय बालक घर में सो रहे थे, तभी अचानक 3.20 बजे अज्ञात नकाबपोश ने घर में घुस कर लाखों की डकैती को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी कमला जोशी बैतूल से मौके पर पहुंचीं। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड की मदद से खबर लिखे जाने तक जांच की जा रही है। अनाज व्यापारी के बेटे नवनीत ने बताया कि उनके पिता और माता अपने कमरे में सोए हुए थे। इस दौरान चार-पांच नकाबपोश छत से अंदर घुसे। उन्होंने दरवाजे की कुंडी तोड़ी और माता-पिता को

उठाकर मारपीट कर अलमारियों की चाबी छुड़ा ली। एक बदमाश द्वारा फरियादी की पत्नी प्रमिला के गले पर चाकू अड़ाकर मंगलसूत्र छीन लिया गया। दो बदमाशों द्वारा फरियादी के साथ गत्ते तथा लोहे के सरिये जैसे हथियार से मारपीट की गई, जिससे फरियादी के सिर में तथा पैरों में चोटें आई है। दोनों के साथ मारपीट कर अलमारी में रखे जेवरात और नगदी लूट ली। टीआई सत्यप्रकाश सक्सेना ने बताया कि लूट की घटना हुई है अभी मौके पर जांच कर रहे है। आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।

वारदात से पहले की हरकतें सीसीटीवी में कैद- सूत्रों के अनुसार घटना से एक दिन पहले वार्ड 16 बोडखी के आसपास के इलाके में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी, जो सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गईं थीं। पुलिस अब उन फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। लूट के बाद घटनास्थल के पड़ोस के घर से दो बाइक भी चोरी हो गई। घटना के तुरंत बाद आमला थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिस पर एडिशनल एसपी कमला जोशी और थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सक्सेना मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इधर इस मामले में एसपी निश्चल एन झारिया ने बताया कि आमला में एक व्यापारी के घर में लूट हुई है, घटना की जांच की जा रही है। डॉग स्क्वायड की टीम से भी मदद लेकर लुटेरों तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं।

घटनास्थल से मिले महत्वपूर्ण सुराग

जांच के दौरान घटनास्थल से आरोपियों की एक जोड़ी चप्पल और एक टार्च बरामद किया गया है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। फरियादी के अनुसार अंदर घुसे चार बदमाशों मे से एक ने मुंह पर लाला छींट वाला रुमाल, दूसरे ने काला रुमाल बांध रखा था। चारों बदमाश कम हाईट के ओर कम उम्र के सांवले से थे और चड्डे पहने हुए थे। उनके दो अन्य साथी घर के बाहर रैकी के लिये खड़े होना बताया गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्र. 363/2025 धारा 310(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले रही है। इधर बेहड़ी मार्ग पर बाइक लावारिस हालत में मिली है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस से गश्त बढाने की मांग की है।

इनका कहना -

6 नकाबपोशों ने वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें लगभग 5 लाख नगद और 4 लाख रुपये के आभूषण चोरी हुए है। दो बाइक भी उनके पड़ोस से चोरी की गई है। पुलिस को घटना स्थल से महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे है। जिनके आधार पर पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है।

- कमला जोशी, एएसपी, बैतूल

इटारसी-बैतूल मार्ग पर कुण्डी टोल प्लाजा से टोल वसूली प्रारंभ

53 कि.मी. मार्ग पर टोल वसूली, टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र मुक्त

बैतूल। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 46 के इटारसी से बैतूल खंड अंतर्गत पैकेज-2 में शाहपुर के ग्राम कुण्डी स्थित टोल प्लाजा से 22 मई से टोल वसूली शुरू कर दी गई है। कुल 74 कि.मी. की परियोजना में से 53 कि.मी. हिस्से पर टोल वसूला जाएगा, जबकि टाइगर कॉरिडोर के अंतर्गत बरेठा घाट, भौरा घाट एवं केसला घाट के 21 कि.मी. मार्ग को फिलहाल टोल से मुक्त रखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भाराराप्रा) द्वारा संचालित इस टोल प्लाजा पर यात्रियों की सुविधा के लिए पेट्रोलिंग वाहन, क्रेन, एंबुलेंस व आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिनका लाभ टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल कर लिया जा सकता है। स्थानीय निवासियों के लिए भी राहत की बात है। टोल प्लाजा से 20 कि.मी. की परिधि में आने वाले स्थानीय गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए मासिक पास की दर मात्र 350 रुपये निर्धारित की गई है। उद्घाटन अवसर पर भाराराप्रा के परियोजना निदेशक मनीष कुमार मीना, प्रबंधक (तक.) वेद प्रकाश, साइट इंजीनियर नीरज सराठे, एस.डी.एम. शाहपुर अभिजीत सिंह उपस्थित रहे।

अधूरे फोरलेन पर स्थित कुंडी टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली अवैध, कांग्रेस हर स्तर पर करेगी विरोध : पांसे

बैतूल। बैतूल से औबेदुल्लागंज फोरलेन पर शाहपुर के पास कुंडी में शुरू किए गए टोल प्लाजा को अवैध वसूली सेंटर करार देते हुए पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने इसे तत्काल बन्द किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि यह फोरलेन का जब पूरा ही नहीं हुआ तो यह कैसे एनएचएआई को कैसे हैंडओवर हो सकता और जब हैंडओवर ही नही हो सकता तो फिर इस पर किस आधार पर टोल टैक्स की वसूली शुरू की जा रही। सुखदेव पांसे का आरोप है कि बैतूल जिले के अंदर और जिले की सीमा पर खम्बारा, मिलानपुर, कोथलकुण्ड, गढ़ा, घोड़ाडोंगरी सहित आधा दर्जन टोल प्लाजा होना, यह साबित करता है कि भाजपा की सरकार बैतूल की गरीब जनता को दुधारू गाय समझकर टैक्स के नाम पर मनमाना दोहन कर रही है। उनका कहना है कि जितने टोल प्लाजा है, इतने प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं है। उनका कहना है कि कुंडी शाहपुर में जो टोल प्लाजा बुधवार से शुरू किया गया, एनएचएआई के ही नियमों के विपरीत है। पूर्व मंत्री पांसे का दावा है कि जब तक बरेठा घाट और भौरा एवं इटारसी के पास का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक यहां टैक्स की वसूली नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि यह फोरलेन जितना भी अब तक निर्मित हुआ है, वह भी रोड नियमों के अनुरूप नहीं है। इसके एलाइनमेंट और गुणवत्ता की किसी एक्सपर्ट एजेंसी से यदि जांच करा ली जाए, तो वह इसे टेक्निकली फेल घोषित कर देगी। पूर्व मंत्री पांसे का कहना है कि उन्हें लोगो से फीडबैक मिल रहा है और आम नागरिक जिस तरह से इसके खिलाफ है, उसे देखते हुए वे जनता की आवाज को हर फोरम पर उठाएंगे तथा कांग्रेस इस मुद्दे पर आंदोलन भी करेगी। आगामी विधानसभा सत्र में इसे वे नेता प्रतिपक्ष से भी उठवायेंगे। कांग्रेस इस अन्यायपूर्ण और अवैध वसूली का पुरजोर विरोध करेंगी।

गर्मी में तेंदूपत्ता संग्राहकों को नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं, वन विभाग की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल

बानाबेहड़ा फड़ केंद्र पर न पेयजल, न प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, फड़ प्रभारी ने भी जताई मजबूरी

बैतूल भौरा। परिक्षेत्र में इन दिनों तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य जोरों पर है। वन परिक्षेत्र भौरा अंतर्गत धार बीट के ग्राम बानाबेहड़ा में इन दिनों तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य जारी है। यहां क्षेत्र के सैकड़ों संग्राहक दिनभर की मेहनत के बाद अपने एकत्र किए गए तेंदूपत्तों को फड़ केंद्र पर जमा कर रहे हैं। लेकिन वन विभाग द्वारा फड़ स्थल पर संग्राहकों के लिए किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई

है, जिससे लोगों को गर्मी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय संग्राहकों ने बताया कि इस भीषण गर्मी में जहां तापमान बड़ा हुआ है, वहीं फड़ पर पानी, छाया और विश्राम की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कई महिलाएं और बुजुर्ग तपती धूप में खड़े होकर घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं।

नियमों की हो रही अनदेखी- राज्य शासन द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य को लेकर स्पष्ट निर्देश हैं कि संग्रहण अवधि के दौरान फड़ स्थलों पर छाया, पीने के पानी, प्राथमिक उपचार सामग्री आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए। मध्यप्रदेश राज्य तेंदूपत्ता (व्यवस्थापन) नियम, 1965 के अनुसार संग्राहकों की सुविधा और स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्णतः वन विभाग की होती है। लेकिन बानाबेहड़ा फड़ पर इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। संग्राहकों ने मांग की है कि तत्काल फड़ स्थल पर पेयजल की व्यवस्था की जाए, अस्थायी टेंट या छाया की व्यवस्था हो और प्राथमिक उपचार बॉक्स की व्यवस्था की भी मांग की गई है। हर साल तेंदूपत्ता संग्रहण से सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन इन पत्तों को तोडने वाले मेहनतकश मजदूरों को ही बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। यदि शीघ्र ही वन विभाग इस ओर ध्यान नहीं देता, तो यह संग्राहकों के स्वास्थ्य और अधिकारों के साथ अन्याय होगा। प्रशासन को इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेकर त्वरित सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।

इनका कहना है -

तेंदू पत्ता फड़ पर पानी की व्यवस्था के लिए हमने फड मुंशी को कहा था। उन्हें ही पानी की व्यवस्था करना था चाय की कोई व्यवस्था इस बार नहीं थी प्राथमिक उपचार के लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध थी अगर किसी को आवश्यकता होती है। तो मैं तुरंत जाकर उन्हें दे देता हूं।

- **राजेंद्र प्रसाद तिवारी** नोडल अधिकारी धार बीट

पानी, छाया एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हर साल रहती है। इस साल भी करी गई थी। अगर वहां उपलब्ध नहीं है तो मैं नोडल से बात करता हूं।

- **अरुण कुमार शुक्ला,** वन परिक्षेत्र अधिकारी भौरा

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गो से निकाली

सुबह सवेरे सोहागपुर। आज शाम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गो से निकाली गई। उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में छिपे आर्तकियों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इस तिरंगा यात्रा में भाजपा नेताओं , कार्यकर्तृताओं के अलावा नगर के विभिन्न तबकों के नागरिक शामिल थे। भाजपा मंडल अध्यक्ष अश्विनी सरोज ने बताया कि सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह के मार्गदर्शन में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा गौतम बुद्ध वार्ड से प्रारंभ हुई। तिरंगा यात्रा पलकमती नदी पुल, मुख्य बाजार, कमानिया गेट, बिहारी चौक, से होकर पुराने थाने के पीछे रानी लक्ष्मीबाई मंच से होकर श्रीराम चौक में विर्सजित हुई। इस यात्रा में भाजपाई राजेश शुक्ला माईक से होंसला अफजाई

कर के भारत माता की जय, जय हिंद एवं वंदे मातरम , भारत माता की जय , पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों को गुंजायमान करवा रहे थे। वहीं नागरिक हाथों में तिरंगा ध्वज थामे हुए चल रहे थे। इस तिरंगा यात्रा में वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी माधव सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमति लता यशवंत पटेल,पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष जयप्रकाश माहेश्वरी, अध्यक्ष प्रतिनिधि यशवंत पटेल, उपाध्यक्ष आकाश रघुवंशी, भाजपा नेता राजेश शुक्ला, संजीव शुक्ला मंडल अध्यक्ष अश्वनी सरोज, कोषाध्यक्ष सौरव सोनी, अरुण चौरसिया, अरविंद रघुवंशी,अभिनव पालीवाल,ऋषभ गढ़वाल रविशंकर उईके, रामबाबू रघुवंशी, पूनम दुबे, पुष्पा वर्मा, शक्ति मेहरा, कविता साहू सहित कई गणमान्य नागरिक एवं भारी संख्या में मातृशक्ति सम्मिलित थीं।

अभिशाप बनकर रह गया सीवर लाइन प्रोजेक्ट

सीवर लाइन के लिए तोड़ी गई सडकों पर पैदल चलना मुश्किल

बैतूल/मुलताई। ताप्ती सरोवर मुलताई मे गंदा पानी जाने से रोकने के लिए लिए 3 वार्डों में 6 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से बना सीवर नेटवर्क प्रोजेक्ट पवित्र नगरी के लिए अभिशाप बनकर रह गया है। सिविल लाइन प्रोजेक्ट के ठेकेदार ने 6 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ से अधिक की सीमेंट कांक्रीट रोड तोड़ दी। नगर पालिका परिसर में ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर बड़ा गड्ढा खोद दिया और लगभग 4 करोड़ का भुगतान लेकर प्रोजेक्ट को अधर में छोडक़र चलता बना। वर्तमान परिषद ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव लिया। पार्षदों ने कहा एफआईआर दर्ज कराएंगे, किंतु चार माह बाद भी ठेकेदार पर ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही प्रोजेक्ट के लिए तोड़ी गई सडक़ों के सुधार के लिए कोई ठोस कार्य योजना हीं बनाई गई। सबसे बड़ी समस्या प्रोजेक्ट के लिए तोड़ी गई, वह सडक़े हैं जो बद से बदत्तर हो गई है। तोड़ी गई सडक़ों का सुधार कार्य भी सीवर लाइन ठेकेदार के जुम्मे था, अब बड़ा प्रश्न यह है कि इन टूटी हुई सडक़ों का सुधार कार्य कौन करें। नगर पालिका के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर

नहीं है दूसरी ओर तोड़ी गई सडक़े आए दिन दुर्घटनाओं का सबब बन रही है। दो पहिया वाहन तो दूर टूटी हुई सडक़ों पर पैदल चलना दुश्वार हो रहा है और वर्षा काल में यह समस्या और भी विकराल रूप धारण कर लेती है।

बंदरबांट की भेंट चढ़ गई महत्वाकांक्षी परियोजना- सीवर लाइन प्रोजेक्ट का उद्देश्य ताप्ती सरोवर में गंदा पानी जाने से रोकना था। पूर्व परिषद एवं अधिकारियों ने योजना को लेकर बड़े-बड़े सपने दिखाए, किंतु भोपाल के टेबल पर बैठकर कंसल्टेंसी द्वारा बनाया गया उक्त योजना का डीपीआर मुलताई नगर के लिए प्रासंगिक है अथवा नहीं यह देखना किसी ने भी आवश्यक नहीं समझा। ठेकेदार ने उक्त कार्य का ठेका 11 प्रतिशत बिल लिया था, निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो निर्माण की गुणवत्ता ठेकेदार पर निर्भर थी और भुगतान करने वालों ने भी यह जानने का प्रयास नहीं किया की जो भुगतान हो रहा है। इसके अनुरूप कार्य हुआ है अथवा नहीं और ठेकेदार यह कार्य भुगतान लेने के बाद पूर्ण कर पाएगा या नहीं। कुल मिलाकर उक्त योजना बंदर बाट योजना बनकर रह गई है और जनता के करोड़ों रुपए सीवर लाइन में बह गए है।

प्रोजेक्ट की शेष राशि बनी पहेली- सीवर लाइन प्रोजेक्ट के लिए शासन से 6 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। विभागीय जानकार बताते हैं कि सिवर लाइन ठेकेदार को तीन से चार करोड रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस स्थिति में योजना की शेष राशि कहां गई इसको लेकर भी ठीक-ठाक जवाब किसी के पास भी नहीं है। पूर्व में तत्कालीन नगर पालिका अधिकारी पर उक्त प्रोजेक्ट की राशि का मद परिवर्तन कर अन्य कार्य में राशि खर्च करने की शिकायत तो हुई, किंतु इसका कोई हल नहीं निकला, अब ठेकेदार को कार्य छोड़ें भी लंबा समय हो गया। इस दौरान वर्तमान नगर परिषद को चाहिए था पूर्व में बढ़ाई गई समय सीमा के आधार पर कार्य न करने पर ठेका निरस्त कर ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करती एवं योजना का उद्देश्य बर्बाद होने और नगर पालिका को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने वाले ठेकेदार पर करवाई कर शेष राशि के संबंध मे जानकारी प्राप्त करती, किंतु परिषद की बैठक में चर्चा के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया।

सीवर लाइन प्रोजेक्ट के लिए टूटी 8 किलोमीटर सड़क ....

एक अनुमान के आधार पर जानकार बताते हैं कि बीते 7 सालों में मुलताई नगर में लगभग 20 करोड़ लागत की सडक़े बनाई गई, जिसमें से अधिकांश सडक़ें पाइपलाइन एवं सीवरेज पाइप बिछाने के लिए तोड़ दी गई। विभागीय सूत्रों की माने तो, मात्र सीवर लाइन प्रोजेक्ट के लिए ही 8 किलोमीटर की सडक़े तोड़ी गई है। सीवर लाइन और पाइप लाइन के लिए तोड़ी गई सडक़े जिनका सुधार कार्य होना अब प्रावधानों के मध्य उलझ कर रह गया है ।

इनका कहना है -

मैं अभी-अभी आया हूं सीवर लाइन प्रोजेक्ट नस्ती का अध्ययन कर रहा हूं, नस्ती अध्ययन के उपरांत ही इस संबंध में कुछ कह पाऊंगा।

- **वीरेंद्र तिवारी,** मुख्य नगरपालिका अधिकारी मुलताई

नर्मदापुरम की भूमि उपजाऊ एवं समृद्ध है जिले के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी: मुख्यमंत्री

सीएम ने किया सिवनी मालवा में 97.07 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 102.94 करोड़ के कार्यों का भूमि-पूजन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नर्मदापुरम जिले की भूमि उपजाऊ एवं समृद्ध है, यहां कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए शासन कृत-संकल्प है। नर्मदापुरम के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कर निवेश को प्रोत्साहित किया गया है। आने वाले समय में नर्मदापुरम औद्योगिक रूप से विकसित जिला बनेगा। मुख्यमंत्री ने गुरूवार को सिवनी मालवा में 97.07 करोड़ के 31 कार्यों का लोकार्पण एवं 102.94 करोड के 48 कार्यों का भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री ने सिवनी मालवा में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नर्मदापुरम जिला ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारे देश की पहचान कृषि से होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों, युवाओं, महिलाओं एवं श्रमिक सभी वर्ग के लिए योजनाऐं बनाई हैं। मध्यप्रदेश शासन भी गरीब वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने दुश्मनों को परास्त किया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति जियो और जीने दो पर आधारित है। पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारा प्रदेश देश के मध्य में है इसलिए हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने इस बार 2600 रूपए प्रति क्विंटल के मान से किसानों से गेहूं खरीदा है। आने वाले समय में हम 05 लाख के सोलर पंप पर 90 प्रतिशत अनुदान देंगे। सोलर पंप में जो मीटर लगेगा उससे किसानों को निःशुल्क में बिजली मिलेगी और आने वाले समय में सरकार किसानों से बिजली भी खरीदेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 26 मई को नरसिंहपुर जिले में किसान उद्योग समागम मेले का आयोजन किया जाएगा। तीन दिवसीय इस मेले में अत्याधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। आने वाले समय में रीवा सतना और चंबल में भी ऐसे ही मेले आयोजित किये जाऐंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शासन ने हर खेत में सिंचाई के लिये पानी पहुचाने का संकल्प लिया है। पहले प्रदेश के 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा थी जिसे बढ़ाकर 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित कर ली गई है। आने वाले समय में 100 लाख हेक्टेयर में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड रही है। नर्मदापुरम जिले के हॉकी खिलाडी विवेक सागर को ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने पर एक करोड की प्रोत्साहन राशि दी गई थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि युवा वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 01 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएगी। साथ ही आगामी 5 वर्षों में ढाई लाख सरकारी पद भरे जाऐंगे। उन्होंने कहा कि विगत 15 वर्षों में इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट सबसे बेहतर आया है। इस वर्ष सरकारी स्कूल के बच्चों ने प्रावीण्य सूची में अपना स्थान बनाया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक अभिनव गोपालक योजना प्रारंभ की जाएगी। जो किसान 200 गिर गाय खरीदेंगे उन्हें 25 प्रतिशत तक की अनुदान राशि दी जाएगी। किसानों से दूध खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य परिवहन निगम की बसें गांव गांव तक जाऐंगी। उन्होने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब आयुष्मान कार्ड धारी गंभीर मरीजों को चिकित्सालय पहुंचाने के लिए एयर एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट को अयोध्या की तरह ही भव्य बनाया जाएगा और जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं उन मार्गो पर तीर्थ स्थान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र एवं उपकरण वितरित किये।

इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री एवं नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं नर्मदापुरम विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा, नरसिंहपुर-होशंगाबाद सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, सोहागपुर विधायक श्री विजयपाल सिंह, पिपरिया विधायक श्री ठाकुरदास नागवंशी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी एवं अन्य जनप्रतिनिधि सहित बडी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं महिलाऐं उपस्थित रहीं।

सिवनी मालवा में भारत के वीर सैनिकों के सम्मान में निकली 'तिरंगा यात्रा'

'भारत माता की जय' और 'वंदे-मातरम्' के उद्घोष से गूंज उठा सिवनी मालवा शहर

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में देश के वीर सैनिकों के सम्मान में आयोजित 'तिरंगा यात्रा' में शामिल हुए। अपार जोश और उल्लास के साथ तिरंगा यात्रा स्थानीय शासकीय कुसुम स्नातकोत्तर महाविद्यालय से प्रारंभ हुई और नर्मदापुरम मार्ग से होकर कृषि उपज मंडी प्रांगण में सम्पन्न हुई।

तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री डॉ. यादव तिरंगे फूलों से सजाए गए विशेष रथ में सवार थे। उन्होंने इस दौरान हाथ हिलाकर नागरिकों का अभिवादन किया। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा शहर राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत हो गया और आसमान 'भारत माता की जय' और 'वंदे-मातरम' के उद्घोष से गुंजायमान हुआ। यात्रा में लोक निर्माण मंत्री एवं नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह, क्षेत्रीय सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, सिवनी मालवा विधायक श्री प्रेम शंकर वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए।

हाथों में राष्ट्रध्वज तिरंगा लिए सभी समुदायों और सभी आयु वर्ग के नागरिक बड़ी संख्या में इस तिरंगा यात्रा में भरपूर उत्साह के साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस दौरान 'तिरंगा यात्रा' में शामिल नागरिकों पर पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षिक संगठनो द्वारा आतिशबाजी की गई और तिरंगा यात्रा में शामिल नागरिकों पर पुष्प वर्षा भी की गई।

एम्स भोपाल में यूवाइटिस मीट 2025

सुपर-स्पेशियलिटी नेत्र चिकित्सा में विशेषज्ञता और सहयोग का संगम

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में नेत्र रोग विभाग द्वारा दिनांक 25 मई, 2025 को यूवाइटिस मीट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन भोपाल डिवीजन ऑप्थैल्मिक सोसाइटी के सहयोग से और यूवाइटिस सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण शैक्षणिक सम्मेलन मध्य भारत में नेत्र चिकित्सा के सुपर-स्पेशियलिटी अभ्यास में एक उल्लेखनीय पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो देश के प्रमुख विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। सम्मेलन में यूवाइटिस और नेत्र सूजन के क्षेत्र में देशभर से प्रसिद्ध विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिनमें डॉ. पद्ममालिनी महेन्द्रदास (प्रमुख, यूवाइटिस एवं ऑक्युलर इम्यूनोलॉजी विभाग, नारायण नेत्रालय, बेंगलुरु), डॉ. पार्थप्रतिम दत्ता मजूमदार (वरिष्ठ सलाहकार एवं निदेशक नवाचार, शंकर नेत्रालय, चेन्नई), डॉ. पुरेन्द्र भसीन (संस्थापक एवं अध्यक्ष, रतन ज्योति नेत्रालय, ग्वालियर तथा अध्यक्ष, मध्यप्रदेश ऑप्थैल्मोलॉजिकल सोसाइटी), डॉ. आलोक सेन (प्रमुख, रेटिना एवं यूवाइटिस, सदगुरु नेत्र चिकित्सालय, चित्रकूट), डॉ. धैवत शाह (प्रमुख, रेटिना एवं संयुक्त चिकित्सा निदेशक, चोईथराम नेत्रालय, इंदौर) तथा डॉ. अनामिका द्विवेदी (एसोसिएट प्रोफेसर, नेत्र रोग विभाग, एसएस मेडिकल कॉलेज, रीवा) शामिल हैं। स्थानीय संकाय की ओर से डॉ. गजेन्द्र चावला, डॉ. गणेश पिल्लै और डॉ. समेन्द्र करखुर भी प्रमुख वक्ता होंगे।

इस सम्मेलन का उद्देश्य नेत्र रोग विशेषज्ञों को यूवाइटिस एवं नेत्र सूजन के सुपर-स्पेशियलिटी अभ्यास की बारीकियों से अवगत कराना है। साथ ही, यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश के रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए एक प्रशिक्षण मंच प्रदान करेगा, जिससे वे अनुभवी विशेषज्ञों से सीखकर अपनी नैदानिक एवं शल्य कौशल को और अधिक दक्ष बना सकें। इस अवसर पर आयोजन अध्यक्ष डॉ. सरोज गुप्ता और सह-अध्यक्ष डॉ. प्रीति सिंह ने कहा कि यह सम्मेलन शंकर नेत्रालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की विशेषज्ञता को भोपाल लाकर नेत्र चिकित्सा समुदाय और रोगियों, दोनों को लाभान्वित करेगा। इसके साथ ही, आयोजन सचिव डॉ. समेन्द्र करखुर ने कहा कि ऐसे वैज्ञानिक संवाद न केवल चिकित्सकीय समुदाय को सशक्त करते हैं, बल्कि अंततः रोगियों के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं, जिनकी सेवा में चिकित्सा जगत निरंतर संलग्न रहता है। प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने सम्मेलन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएँ देते हुए कहा, एम्स भोपाल अकादमिक उत्कृष्टता, अनुसंधान, सहयोग और निरंतर संवाद को हमेशा प्रोत्साहित करता रहा है। 'यूवाइटिस मीट 2025' नेत्र रोगों की सुपर-स्पेशियलिटी क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। देशभर के प्रमुख विशेषज्ञों की भागीदारी इसे हमारे चिकित्सकों और छात्रों के लिए सीखने, नवाचार करने और जटिल नेत्र रोगों से ग्रसित रोगियों की देखभाल में सुधार लाने का एक अनमोल अवसर बनाती है।

प्रधानमंत्री के रेलवे स्टेशन के उद्घाटन समारोह में उपमुख्यमंत्री शुक्ल, सांसद वी.डी. शर्मा हुए शामिल

भोपाल। उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि समाज के हर वर्ग को खासतौर पर गरीब और मध्यम वर्ग को सभी प्रकार की सुविधाएं मिले। कटनी साउथ रेलवे स्टेशन का जो कायाकल्प हुआ है उससे यह अत्याधुनिक सुविधायुक्त स्वरूप में नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हम विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आज विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कौशल संवर्धन की दिशा में गंभीर प्रयास हो रहे है। उन्होंने कहा कि कटनी में खुलने वाले पीपीपी मोड के मेडिकल कॉलेज के प्रति सर्वाधिक कंपनियों एवं संस्थानों ने दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने कहा कि कटनी का जिला चिकित्सालय शासकीय स्वरूप में यथावत कार्य करता रहेगा। यहां मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा और दवाईयां पूर्ववत मिलती रहेंगी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम से कटनी साउथ रेलवे स्टेशन सहित देश के 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। कटनी साउथ अमृत रेलवे स्टेशन में उपमुख्यमंत्री श्री शुक्ल, सांसद खजुराहो श्री वी.डी. शर्मा, यात्री सुविधाओं से युक्त, अत्याधुनिक और नये स्वरूप में बने अत्यंत सुंदर और भव्य रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के साक्षी बने।

सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि कटनी साउथ रेलवे स्टेशन की भव्यता का स्वरूप वास्तव में प्रधानमंत्री श्री मोदी और केन्द्रीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव की परिकल्पना है। उन्होंने कहा कि कटनी में ही एशिया का पहला ग्रेड सेपरेटर यानि रेलवे का ओवरब्रिज बना है। सांसद श्री शर्मा ने कहा कि इन सभी बड़ी योजनाओं के रूप में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कटनी को सौगात दी है। सांसद श्री शर्मा ने कहा कि कटनी रेलवे को सर्वाधिक रेवन्यू देने में शामिल है। कटनी के विकास में रेलवे का अहम योगदान है।

विधायक विजयराघवगढ़ श्री संजय पाठक पाठक, विधायक मुड़वारा श्री संदीप जायसवाल, विधायक बड़वारा श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, महापौर श्रीमती प्रीति सूरी ने भी संबोधित किया। डीआरएम श्री कमल तलरेजा, एरिया मैनेजर रेलवे श्री रोहित सिंह, सीनियर डीसीएम मधुर वर्मा एवं पूर्व राज्य मंत्री श्रीमती अलका जैन सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कटनी साउथ रेलवे स्टेशन- कटनी साउथ रेलवे स्टेशन, जिसे अब आधुनिक सुविधाओं और सांस्कृतिक पहचान के साथ नया स्वरूप प्रदान किया गया है, 12.88 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने स्वतंत्रता, शौर्य और स्वाभिमान के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है।

पुनर्विकास कार्यों में स्टेशन भवन का नवनिर्माण, भव्य प्रवेश द्वार, विकसित प्रतीक्षालय, पर्याप्त टिकटिंग काउंटर, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय एवं रैम्प, दोनों ओर के हाई लेवल प्लेटफॉर्म पर कवर शेड्स शामिल हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्गीकरण किया गया है और आधुनिक एलईडी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। कटनी साउथ स्टेशन अब सिर्फ एक रेलवे हब नहीं बल्कि आधुनिक भारत की झलक प्रस्तुत करता है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस विकास से स्थानीय यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र गतिविधियों और सांस्कृतिक समृद्धि को भी गति मिलेगी।

गर्मी से बचाव हेतु एम्स भोपाल ने चलाया 'बीट द हीट' अभियान

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में एम्स भोपाल द्वारा बीट द हीट नामक जनजागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों, रोगियों एवं आगंतुकों को भीषण गर्मी से बचाव के उपायों की जानकारी देना है। इस अभियान की टैगलाइन है- हटेगी गर्मी जीतेंगे हम । यह अभियान विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमारी ग्रसित लोगों जैसे संवेदनशील समूहों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से शुरू किया गया है। अभियान के अंतर्गत अस्पताल परिसर में जानकारीपूर्ण पोस्टर और डिजिटल डिस्प्ले लगाए गए हैं, जिनमें विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जो गर्मी से बचने में सहायक हो सकते हैं। इन सुझावों में तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाना और हीट स्ट्रोक के लक्षणों पर ध्यान देना, खुली धूप और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना, ताजा एवं पौष्टिक भोजन करना, स्वच्छ पानी पीना और छाया में रहना, तथा लू लगने से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेना शामिल है।

अभियान के संबंध में प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा, बढ़ते तापमान को देखते हुए यह आवश्यक है कि सभी लोग आवश्यक सावधानियाँ बरतें। इस अभियान के माध्यम से हमारा उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि कुछ आसान उपायों को अपनाकर हम गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं। एम्स भोपाल जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सतत् प्रयासरत है।÷ यह अभियान मौसमी चुनौतियों के दौरान स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और नागरिकों को सुरक्षित रखने की एम्स भोपाल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग

बैतूल। जैव विविधता दिवस के अवसर पर मप्र जन अभियान परिषद व माय भारत द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रत्याशा फाउंडेशन की तुलिका पचौली व समाजसेवी पिंकी भाटिया की उपस्थिति में और माई भारत जिला युवा अधिकारी श्रीमती सुषमा गवली की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर तूलिका पचोली ने कहा कि जंगलों से जीव जंतु खत्म हो रहे हैं जो जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग है। जिला युवा अधिकारी माय भारत ने कहा कि आज जीवो को संरक्षण को लेकर सरकार अहम भूमिका निभा रही है जिसमें हम सभी को भी पहल करने की आवश्यकता है। भूपेंद्र पवार ने बताया कि आज हम कीटनाशकों का उपयोग कर जीवों को तेजी से नष्ट कर रहें है जो चिंता का विषय है। धनंजय सिंह ठाकुर ने माई भारत सिविल डिफेंस पंजीयन की जानकारी से अवगत कराया।

टी बी मुक्त भारत अभियान के लिए हुई बैठक

फोकस बेस्ड एप्रोच आधारित गतिविधियों पर होगा जोर: सीएमएचओ

भोपाल। टीबी मुक्त भारत अभियान की तैयारियों को लेकर मैदानी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई । बैठक में टीबी उन्मूलन के लिए फोकस्ड एप्रोच पर कार्य करने की रणनीति पर चर्चा की गई। जिसके तहत मधुमेह के मरीजों, कुपोषित, धूम्रपान करने वाले, शराब सेवन करने वाले, पूर्व टीबी मरीज, संपर्क व्यक्ति और एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को लक्षित कर गतिविधियों का आयोजन किए जाने पर जोर दिया जाएगा।

टीबी मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य उच्च जोखिम वाले मरीजों की स्क्रीनिंग, जांच, और उपचार प्रदान करना है। इसके पूर्व प्रदेश के 23 उच्च-प्राथमिकता वाले जिलों में 100 दिवसीय निक्षय शिविरों का आयोजन 7 दिसंबर से 25 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। जिसे विस्तार देते हुए पूरे प्रदेश में अभियान संचालित किया जा रहा है।

अभियान के तहत पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, स्वसहायता समूहों, जन आरोग्य समिति, महिला आरोग्य समिति, ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता समिति के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नए निक्षय मित्रों और टीबी चैंपियंस/विजेताओं की पहचान की जाएगी, ताकि उनकी सहभागिता से अभियान को और गति दी जा सके। त्योहारों और मेलों के दौरान धार्मिक गुरुओं के माध्यम से जागरूकता संदेश प्रसारित किए जाएंगे, और स्कूलों और कॉलेजों में कला और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, रैलियाँ आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा, टीबी शपथ के आयोजन, स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य सरकारी विभागों में नि-क्षय सप्ताह के आयोजन के तहत जागरूकता सत्र, निक्षय शिविर, प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी।

जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी डॉ प्रांजल खरे ने बताया कि अभियान के तहत विभिन्न शिविरों का आयोजन प्रमुख सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे और बस स्टेशनों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जाएगा। नि-क्षय शिविरों का आयोजन कारखानों, उद्योगों, ईंट भट्टों, निर्माण स्थलों, क्रेशरों पर किया जायेगा, ताकि श्रमिक वर्ग और अन्य संवेदनशील वर्गों तक इस अभियान का लाभ पहुँच सके।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अभियान का उद्देश्य टीबी उन्मूलन के प्रयासों को और अधिक गति देना और जन-जागरूकता को बढ़ावा देना है। अभियान के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों और टी.बी. के मरीजों की स्क्रीनिंग, जांच एवं जागरूकता गतिविधियां की जाएगी।

जिला और प्राथमिक स्तर पर रक्तस्राव विकारों के लिए विशेष सेवाओं का किया जा रहा है विस्तार : डॉ. सिडाना

हीमोफिलिया रोगियों के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण उपचार की दिशा में ठोस रणनीति पर सहमति बैठक में किया गया मंथन

भोपाल। मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश डॉ. सलोनी सिडाना ने कहा कि मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली को समावेशी और रोगी-केंद्रित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें हीमोफिलिया, सिकल सेल और अन्य गैर-संचारी रोगों को समान प्राथमिकता मिल रही है। एनएचएम द्वारा जिला और प्राथमिक स्तर पर रक्तस्राव विकारों के लिए विशेष सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में हम एक हीमोफिलिया रजिस्ट्री तैयार कर रहे हैं। इसे अधिक गतिशील और पोर्टेबल बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि रोगियों को किसी भी जिले में निर्बाध उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि क्लॉटिंग फैक्टर थेरेपी उपचार की आधारशिला है, लेकिन एमिसिजुमैब जैसी नॉन-फैक्टर थेरेपी अब संभावनाओं के नए द्वार खोल रही हैं, जिन्हें हमें राज्य की सेवा प्रणाली में सम्मिलित करने के तरीके तलाशने होंगे। इसके लिए रोगियों और स्वास्थ्यकर्मियों दोनों में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है।

एनएचएम भोपाल, हीमोफिलिया सोसाइटी, मध्यप्रदेश चैप्टर (भोपाल), गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश में हीमोफिलिया से पीड़ित मरीजों के लिए समान, सुलभ और प्रभावी उपचार ढांचे की दिशा में ठोस नीति तैयार करने के उद्देश्य से एक दिवसीय सहमति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हीमोफिलिया के उपचार और प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं। प्रमुख राष्ट्रीय हेमेटोलॉजिस्ट, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नीति निर्माता, रोगी प्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।

डॉ. आर.के. निगम, एल.एन. मेडिकल कॉलेज, भोपाल, ने बताया कि प्रदेश में करीब 1,000 पंजीकृत हीमोफिलिया रोगी हैं, जबकि वास्तविक संख्या कहीं अधिक हो सकती है। उन्होंने बेहतर निदान और राज्यव्यापी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना पर जोर दिया। डॉ. रूबी खान, डिप्टी डायरेक्टर, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश ने कहा कि हीमोफिलिया का सही समय पर निदान, नियमित रिप्लेसमेंट थेरेपी और मजबूत रेफरल प्रणाली हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हर अनुपचारित रक्तस्राव न केवल रोगी के जीवन की गुणवत्ता पर असर डालता है, बल्कि हमारी स्वास्थ्य प्रणाली की कमजोरी को भी दर्शाता है।

डॉ. नरेश गुप्ता, प्रबंध निदेशक, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, ने कहा कि नियमित रिप्लेसमेंट थेरेपी जोड़ों की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता के लिए अनिवार्य है। उन्होंने एमिसिजुमैब जैसी उन्नत नॉन-फैक्टर थेरेपी को दुर्गम क्षेत्रों और विशेष मामलों में प्रभावी समाधान बताया। पैनल चर्चाका संचालन वरिष्ठ हेमेटोलॉजिस्ट डॉ. तुलिका सेठ ने किया। उन्होंने कहा कि हर अनुपचारित रक्तस्राव रोगी के जीवन से औसतन 16 दिन छीन लेता है। यह आवश्यक है कि हम साक्ष्य-आधारित राज्य-समर्थित दिशानिर्देशों को अपनाएं और प्रोफिलैक्सिस को व्यापक रूप से लागू करें।

डॉ. वरुण कौल, सहायक प्रोफेसर, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ने बताया कि एमिसिजुमैब जैसी नॉन-फैक्टर थेरेपी के माध्यम से हीमोफिलिया ए प्रबंधन में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हो रहा है, जिससे रक्तस्राव की घटनाओं में भारी कमी देखी जा रही है। प्रोफिलैक्सिस को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के ढांचे में एकीकृत करने और राज्य में इसकी समान उपलब्धता सुनिश्चित करने का विशेषज्ञों ने सुझाव दिया। विशेषज्ञों ने कहा कि यदि संरचित तरीके से प्रोफिलैक्सिस और नॉन-फैक्टर थेरेपी का विस्तार किया जाए तो हीमोफिलिया रोगियों को एक स्वस्थ और पूर्ण जीवन प्रदान किया जा सकता है।

25 मई से नौतपा, इस बार इन 9 दिनों में मिल रहे हैं 3 बड़े संकेत

भोपाल। नौतपा भीषण गर्मी के प्रचंड 9 दिनों को कहा जाता है। नौतपा में लू चलती है और भीषण गर्मी में ऐसा लगता है जैसे आसमान से आग उगल रही हो। विष्णु पुराण में नौतपा यानी प्रचंड गर्मी को कई संकेतों से जोड़कर देखा जाता है। सीहोर के ज्योतिष डॉ पंडित गणेश शर्मा के अनुसार सूर्यदेव जब धरती से पूरी नमी सोख लेंगे, तो पृथ्वी कछुए की पीठ की तरह शुष्क नजर आएगी। विष्णु पुराण में प्रचंड गर्मी के बारे में ऐसी ही भविष्यवाणियां की गई हैं, जो समय बीतने के साथ सच होती दिख रही है।

हाल ही में बढ़ती गर्मी ने जिस तरह से अपना शुरुआती रूप दिखाया है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे आने वाला समय कितना घातक हो सकता है।

नौतपा में सूर्यदेव धरती तपाएंगे। खासतौर पर बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोग इस बात का अंदाजा लगा चुके हैं कि इस साल नौतपा कितना खतरनाक हो सकता है। नौतपा का अर्थ संक्षेप में समझें, तो मई के आखिर या जून की शुरुआत में प्रचंड गर्मी पड़ती है। इस दौरान तेज लू चलती है। इसे ही ओनौतपा कहते हैं।

विष्णु पुराण में भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, जिसे लोग प्रचंड गर्मी और नौतपा से जोड़कर देखते है धार्मिक और पौराणिक महत्व और नौतपा से जुड़े संकेत।

ग्वालियर में विधवा बहू की सास ने कराई दूसरी शादी

कहा- पति होते तो यही फैसला लेते, स्वर्गीय कवि प्रदीप चौबे के बड़े बेटे ने किया कन्यादान

ग्वालियर (नप्र)। ग्वालियर में एक सास ने अपनी छोटी बहू का दूसरा विवाह करके मिसाल पेश की है। विधवा बहू की पीड़ा को देखते हुए उन्हें उसकी जिंदगी फिर से बसाने का निर्णय लिया। समाज की पुरानी सोच और परंपराओं को तोड़ते हुए उन्होंने यह फैसला लिया और मां की भूमिका निभाते हुए बहू की दूसरी शादी करवाई।

दरअसल, ग्वालियर के जाने माने हास्य कवि स्वर्गीय प्रदीप चौबे के दो बेटे हैं। उनके छोटे बेटे

आभास का भोपाल में 7 साल पहले एक सड़क हादसे में मौत हो गई। इस घटना के कुछ समय बाद ही कवि प्रदीप चौबे का भी निधन हो गया।

घर में उनकी पत्नी विनीता चौबे और छोटी बहू वर्षा का एक-एक दिन मुश्किल भरा गुजर रहा था। तभी सास विनीता ने ठान लिया कि वे फिर से बहू का जीवन आबाद करेंगी। परिवार, छोटी बहू वर्षा और बड़े बेटे की सहमति के बाद 11 मई को वर्षा का विवाह कानपुर के चेतन जैन करवाया। इस पूरे विवाह में खास बात यह है कि सास विनिता के बड़े बेटे और बहू ने वर्षा का कन्यादान किया।

अगर पति जिंदा होते तो वो भी बहू की दूसरी शादी जरूर कराते- मीडिया ने स्वर्गीय कवि प्रदीप चौबे की पत्नी विनीता उनके इस फैसले को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अगर पति जीवित होते तो वे भी वर्षा की दूसरी शादी जरूर कराते। वह बहू तो थी, पर बेटी से कम नहीं? बड़े बेटे आकाश व बहू नेहा ने भी मेरे भी फैसले में सहयोग दिया।

उन्हीं दोनों ने वर्षा का कन्यादान किया। अब वह हमेशा खुश रहे। विधवा विवाह कर सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने वालीं विनीता चौबे के इस फैसले का स्वागत हर कोई कर रहा है। बहू की दूसरी शादी में अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि सुरेन्द्र शर्मा, अरुण जैमिनी और डॉ. सुरेश अवस्थी भी साक्षी बने।

लोगों ने फैसले का स्वागत किया- युवा हास्य कवि चिराग जैन ने सोशल मीडिया पर इस अनूठी पहल को लेकर पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा, प्रदीप चौबे जी कि पत्नी ने अपने कष्ट भुलाकर युवा बहू की ओर देखा दोबारा शादी का फैसला लिया। यह इतना आसान नहीं रहा होगा।

25 साल बाद फिर विदिशा लोकसभा में पदयात्रा करेंगे शिवराज

केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने 25 मई से रोज 25 किमी पैदल चलेंगे

भोपाल (नप्र)। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 25 साल बाद एक बार फिर विदिशा संसदीय क्षेत्र में पदयात्रा करने जा रहे हैं। 25 मई से शिवराज सिंह चौहान की यह पदयात्रा शुरू होगी।

रोज 25 किमी पैदल चलेंगे- चौहान अपने विदिशा संसदीय क्षेत्र में 25 मई से रोजाना 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे। इस दौरान वे स्थानीय ग्रामीणों को केन्द्र सरकार की योजनाओं के संबंध में चर्चा करेंगे। शिवराज की यह यात्रा केन्द्र सरकार की योजनाओं से हितग्राहियों को जोड़ने के लिए की जाएगी।

1991 में की थी विदिशा लोकसभा क्षेत्र में पदयात्रा- शिवराज सिंह चौहान ने 1991 में पूरे विदिशा लोकसभा क्षेत्र की पदयात्रा की थी। इस पदयात्रा के बाद उनको क्षेत्र के लोग पांव-पांव वाले भैया के नाम से पुकारने लगे थे। अब करीब 25 साल बाद वे फिर से पदयात्रा निकालने जा रहे हैं।

हर सप्ताह दो-तीन दिन करेंगे पदयात्रा- आमतौर पर शिवराज सिंह चौहान शनिवार और रविवार को विदिशा संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आते हैं। वे कार से दौरे करते हैं लेकिन, अब वे पदयात्रा करते हुए अपने क्षेत्र के लोगों के बीच जाएंगे। यह

पदयात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक पहल है। इस दौरान शिवराज सिंह गांव में ही रात्रि विश्राम करेंगे।

विदिशा के बाद देश के दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में भी करेंगे पदयात्रा- यह पदयात्रा लगातार चलेगी और शुरुआत में विदिशा संसदीय क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में यात्रा निकलेगी। इसके बाद देश के दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में भी शिवराज सिंह पदयात्रा निकालेंगे। यात्रा के दौरान गांवों में विभिन्न वर्गों से संवाद कर योजनाओं की जानकारी देंगे, लाभ सुनिश्चित कराएंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण के निर्देश देंगे।

लाभार्थियों से फीडबैक भी लेंगे- पदयात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देंगे, लाभार्थियों से संवाद करेंगे और योजनाओं के प्रभाव का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से वे ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, कृषि सुधार, रोजगार सृजन तथा सामाजिक कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को धरातल पर उतारेंगे।

केंद्र की योजनाओं का प्रचार-प्रसार

पदयात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, ग्रामीण सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, डिजिटल इंडिया, और स्वरोजगार से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी आमजन तक पहुँचाई जाएगी।

लाभार्थियों से करेंगे प्रत्यक्ष संवाद

शिवराज सिंह चौहान लाभार्थियों से मिलकर योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत जानेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसमें स्थानीय भागीदारी भी रहेगी। साथ ही, कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के अधिकारियों के अलावा पंचायत प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह, किसान संगठन, महिला मंडल आदि को भी यात्रा में शामिल कर सबकी सहभागिता की जाएगी और योजनाओं के प्रभाव को व्यापक बनाया जाएगा।

2 साल बाद खुलेंगे नए नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग काउंसिल ने शुरू की आवेदन की प्रक्रिया

भोपाल (नप्र)। नर्सिंग कॉलेजों में बड़े पैमाने पर हुए फर्जीवाड़े और सीबीआई जांच के बाद अब दो वर्षों के अंतराल पर मध्य प्रदेश में फिर से नए नर्सिंग कॉलेजों को अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वर्ष 2022-23 के बाद पहली बार नए कॉलेज खोलने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जून में यह स्पष्ट होगा कि कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2022-23 में जब अंतिम बार नए नर्सिंग कॉलेजों की अनुमति दी गई थी, तब कॉलेजों में मापदंडों की अनदेखी और फर्जी मान्यता संबंधी मामलों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

ला स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी थी। जांच में सामने आया कि कई कॉलेज बिना बुनियादी ढांचे और योग्य स्टाफ के संचालित हो रहे थे। इसके बाद 550 से अधिक कॉलेजों में से लगभग आधे को बंद कर दिया गया।

नए नियम और कसावट के साथ मान्यता

अब नए सत्र 2024-25 में केवल 227 कॉलेजों की मान्यता का नवीनीकरण हो सका है। इस कारण प्रदेश में नर्सिंग स्टाफ की कमी की आशंका जताई जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नए कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है, जिनमें 27 शासकीय नर्सिंग कॉलेज शामिल होंगे। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के अनुसार, नए कॉलेजों को वर्ष 2018 के मापदंडों के तहत ही मान्यता दी जाएगी। आधार आधारित फैकल्टी सत्यापन और कॉलेज की गूगल लोकेशन अनिवार्य की जाएगी। साथ ही, निरीक्षण दल में प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित किए जाएंगे। कड़े नियमों के कारण इस बार 50 से 100 के बीच ही नए कॉलेजों को अनुमति मिलने की संभावना जताई जा रही है।

विभागों को बैंक खातों में जमा राशि बताने के आदेश

फाइनेंस ने तीन दिन में मांगी डिटेल, योजनाओं के लिए नकद फंड का ब्यौरा भी मांगा

भोपाल (नप्र)। प्रदेश सरकार के अलग-अलग विभागों की ओर से बैंकों में कितनी राशि जमा करके रखी गई है। इसकी जानकारी राज्य शासन ने विभाग प्रमुखों से मांगी है। इसके साथ ही कहा है कि सरकार द्वारा बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं पर लिए गए नीतिगत फैसलों के चलते भविष्य में कितने फंड की जरूरत होगी, इसकी भी जानकारी दी जाए। इसके साथ ही सरकार द्वारा लोन और एडवांस के बारे में भी विस्तार से जानकारी देने के लिए कहा गया है। वित्त विभाग ने कहा है कि सभी विभाग यह ब्यौरा जल्द से जल्द भेजें ताकि इसकी रिपोर्ट सरकार के साथ ऑडिटर जनरल को भी भेजी जा सके।

ऑडिटर जनरल भी मांग चुके हैं जानकारी

सरकार के कामकाज के हिसाब की गलतियां पकड़ने और उसमें सुधार कराने की जिम्मेदारी निभाने वाले महालेखाकार भी इस तरह की जानकारी राज्य सरकार से मांग चुके हैं। ऑडिटर जनरल द्वारा 31 मार्च की स्थिति में पहले अप्रैल में ही जानकारी देने को कहा गया था लेकिन विभागों की ओर से ब्यौरा नहीं मिला तो इसकी टाइम लिमिट बढ़ाकर 2 मई कर दी। इसके बाद भी अभी तक विभाग जानकारी नहीं दे सके हैं।

संचालक बजट ने सभी विभागों के बजट नियंत्रण अधिकारी, एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि वर्ष 2024-25 में हुए खर्च और अन्य जानकारी देने के लिए पूर्व में भी विभागों को निर्देश जारी किए गए थे और इसके लिए 2 मई तक की छूट भी दी गई थी लेकिन विभागों की ओर से जानकारी आना बाकी है। सरकार ने यह जानकारी विभागों से 31 मार्च 2025 की स्थिति में मांगी है। इसलिए तीन दिन के भीतर फाइनेंसियल डिटेल भेजी जाए। इसके बाद विभागों के वित्तीय सलाहकारों और वित्त अधिकारियों के साथ वित्त विभाग द्वारा समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी।

यह प्रमुख जानकारी देना जरूरी

● ऑफ बजट लायबिलिटीज ● अनपेड बिलों की लायबिलिटीज ● फंड आपरेटेड आउटसाइड गवर्नमेंट अकाउंट्स ● विभागों की बैंकों में जमा राशि ● पंचायत राज संस्थाओं को दिए गए ग्रांट पर बकाया ● पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में निवेश की राशि का ब्यौरा ● बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं पर लिए गए नीतिगत फैसलों के चलते भविष्य में कितने फंड की जरूरत ● सिंचाई परियोजनाओं पर हुए खर्च की स्थिति, कितना भुगतान हुआ, कितना होना बाकी ● बिजली योजनाओं पर हुए खर्च का ब्यौरा ● अपूर्ण कार्यों की सूची और होने वाला खर्च ● सरकार द्वारा विभिन्न विभागों को कितना अनुदान दिया गया ● रिजर्व फंड की स्थिति

यह जानकारी भी देना होगी

● पिछले वित्त वर्ष में दिए गए लोन और एडवांस की डिटेल ● लोन और एडवांस की ऋणी समूहवार और क्षेत्रवार जानकारी ● निगम, मंडल, कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं को सरकार द्वारा कितना लोन दिया गया ● पिछले सालों में हुए खर्च और उसके समायोजन की पूरी रिपोर्ट ● सरकार ने अनुदान किस काम के लिए दिया, इसकी डिटेल रिपोर्ट ● जिन खातों को बंद किया गया है, उसमें जमा राशि का समायोजन कहां किया गया है।

इंदौर-बैतूल हाईवे पर सड़क हादसे में तीन की मौत

दो बाइकों की भिड़ंत से नीचे गिरे लोगों को ट्रक ने कुचला

देवास (नप्र)। सड़क हादसों के लिहाज से इंदौर-बैतूल हाईवे के डेंजर जोन कलवार घाट में गुरुवार दोपहर दर्दनाक हादसा हो गया। दो बाइक की भिड़ंत के बाद इनमें सवार 6 लोग नीचे गिर गए। ट्रक की चपेट में आने से तीनों लोगों की मौत हो गई। तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका प्राथमिक इलाज कन्नौद में किया गया। मृतकों में दो पुरुष व एक महिला शामिल है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कलवार घाट पर कन्नौद की ओर के उतार वाले क्षेत्र में तेज गति से जा रही दो बाइक के बीच में भिड़ंत हो गई। दोनों बाइक पर तीन-तीन लोग सवार थे। बाइक टकराने के बाद सभी छह लोग नीचे गिर गए।

इनमें से तीन को पास से निकल रहे ट्रक ने चपेट में ले लिया। इससे एक बाइक में सवार पुरुष तथा दूसरी बाइक में सवार एक महिला व एक पुरुष की मौके पर मौत हो गई वहीं हादसे में तीन अन्य गंभीर लोग रूप से घायल हुए इनमें से एक को प्राथमिक उपचार करके रेफर किया गया।

शादी समारोह से लौटते समय हुआ हादसा

शासकीय अस्पताल कन्नौद से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बहिरावद निवासी 25 वर्षीय सनी पुत्र भूरा मर्सकोले की सड़क हादसे में मौत हुई है। उसके साथी मनीष पुत्र गोपाल और छोटू पुत्र रशीद दोनों निवासी ग्राम बहिरावद गंभीर रूप से घायल हुए। यह तीनों लोग शादी समारोह में शामिल होने ग्राम बावड़ीखेड़ा गए थे। वहां से वापस आते समय हादसे का शिकार हुए।

दूसरी बाइक पर एक पुरुष, दो महिलाएं सवार थी, जिनमें से पुरुष व एक महिला की मौत हो गई। दूसरी महिला को गंभीर हालत में रेफर किया गया है। दोनों मृतकों की पहचान के प्रयास किये जा रहे हैं।

भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ब्लास्ट केस में जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

जुवेनाइल बोर्ड में व्यस्क आरोपी की तरह चलेगा नाबालिग पर ट्रायल, जिला कोर्ट ने मांगा था ओपिनियन

जबलपुर (नप्र)। मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले में वर्ष 2017 में हुए बहुचर्चित भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अपराध में शामिल 17 साल के नाबालिग आरोपी के खिलाफ भले ही मुकदमा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलेगा, लेकिन ट्रायल उसे वयस्क मानकर ही किया जाएगा।

दरअसल इस मामले पर भोपाल की जिला अदालत ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से सलाह मांगी थी। उसी को आधार मानकर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। भोपाल कोर्ट ने हाईकोर्ट से यह स्पष्ट करने की मांग की थी कि 17 वर्षीय आरोपी का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत में चलाया जाए या फिर किशोर न्याय बोर्ड में। ट्रायल के दौरान एजेंसी की और से बताया गया था कि जुवेनाइल कोर्ट ने आरोपी की मानसिक और शारीरिक स्थिति का आकलन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला था कि आरोपी वयस्कों की तरह पूर्व रूप से परिपक्व है।

जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि कानूनी रूप से नाबालिग आरोपी की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में ही की जानी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने आरोपी को वयस्क मानकर उसकी ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में ही जारी रखने का फैसला सुनाया है। इस केस में कोर्ट मित्र अनिल खरे और एनआईए की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर दीपेश जोशी उपस्थित रहे।

कोर्ट को बताया गया कि साल 2017 में भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में शाजापुर के पास एक बम धमाका हुआ था। ब्लास्ट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, इसके साथ ही 11 अन्य लोगों को भी धमाके में चोट आई थी। एनआईए ने जांच के दौरान धारा 120-बी, 122, 307, 326, 324; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4; रेलवे अधिनियम की धारा 150, 151; सार्वजनिक संपत्ति (रोकथाम) अधिनियम की धारा 4; और गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम की धारा 16 (बी), 18, 25, 38 और 39 के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

7 मार्च 2017 को हुआ था ब्लास्ट

- 7 मार्च 2017 को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन (59320) सुबह 6:25 बजे तय समय से भोपाल स्टेशन से रवाना हुई।
- सुबह 9:38 बजे शाजापुर जिले के कालापीपल के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन में ब्लास्ट हुआ।
- इसमें नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई।
- कुछ लोग ट्रेन से कूद गए। उसकी वजह से उन्हें चोटें आईं।
- ब्लास्ट की आवाज सुनकर कुछ लोगों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका।
- 14 मार्च 2017 को केंद्र सरकार ने मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी।
- जांच में सामने आया कि आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों ने बम प्लांट किया था।
- जांच एजेंसियों ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सभी नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

एमपी में कहीं लू, तो कहीं आंधी-बारिश, 60 किमी घंटा तक रहेगी हवा की रफ्तार

रायसेन के मंडीदीप में 18 खंभे उखड़े, 60 गांव में बिजली थी गुल

भोपाल (नप्र)। मई महीने में मध्यप्रदेश में सावन-भादौ जैसा मौसम है। भोपाल, इंदौर समेत कुल 46 जिलों के 170 शहर या कस्बों में पिछले 24 घंटे में बारिश हुई। पन्ना में करीब 3 इंच पानी गिर गया। वहीं, खरगोन के भगवानपुरा में 2 इंच से ज्यादा बारिश हुई।

बुधवार को रायसेन के मंडीदीप में आंधी से 18 बिजली के खंभे उखड़ गए। करीब 60 गांव में बिजली गुल हो गई। देर रात छतरपुर और मुरैना में तेज आंधी में पेड़ गिर गए, जिससे बिजली के तार टूट गए। मुरैना में टिन उड़कर एक महिला के चेहरे पर लगा, जिससे वह घायल हो गई। छतरपुर के नौगांव में तेज हवा से एक बुजुर्ग महिला छत से गिर गई। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई।

कहीं-कही ऐसा ही मौसम गुरुवार को भी बना था। ग्वालियर-चंबल संभाग में लू और भोपाल, इंदौर समेत 35 जिलों में आंधी-बारिश

का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में लू चलने का अलर्ट है।

वहीं, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ में आंधी का ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रतिघंटा तक रह सकती है।

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, सीहोर, शाजापुर, देवास, धार और रतलाम में तेज आंधी और बारिश होने की संभावना है।

13 जिलों में आंधी-बारिश, ओले भी गिरे- प्रदेश के 13 से ज्यादा जिलों में बुधवार को आंधी-बारिश का दौर रहा। कुछ जिलों में ओले भी गिरे। भोपाल-इंदौर में दोपहर तक तेज गर्मी रही, लेकिन इसके बाद हल्की बारिश शुरू हो गई। सीहोर के कई गांवों में ओले गिरे। रतलाम, विदिशा में तेज आंधी वाला मौसम रहा। धार, रतलाम, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, रायसेन, रीवा, सागर, बालाघाट में भी बारिश का दौर चलता रहा। होशंगाबाद रोड पर मंडीदीप और औबेदुल्लागंज के बीच 10 से ज्यादा बिजली के पोल तेज हवा से झुक गए।

इधर, छतरपुर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। खजुराहो में पारा 46 डिग्री और नौगांव में 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। टीकमगढ़ में 44.5 डिग्री, गुना में 44.4 डिग्री, शिवपुरी में 44.2 डिग्री, सतना में 43.6 डिग्री, दमोह में 42 डिग्री, सीधी में 41.9 डिग्री, उमरिया, रीवा-सागर में 41 डिग्री और मंडला में 40.2 डिग्री दर्ज किया गया।